



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 17, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1929/वि०स०/संसदीय/171(सं)-2022

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 6 दिसम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा अनुरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होगा।

(3) यह किसी भी क्षेत्र में ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

परिभाषायें

2- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे किसी अधिकारी से है, जो इस अधिनियम की धारा 45में यथा परिभाषित अग्निशमन अधिकारी से कम से कम 02 रैंक उच्चतर हो;

(ख) 'भवन' का तात्पर्य वही होगा जो उसके लिए सुसंगत नगरपालिका विधि अथवा उस क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में समनुदेशित हो, और इसमें भूमि या भवन या किसी प्राधिकृत या अन्यथा रूप में भूमि या भवन के आंशिक भाग से समाविष्ट स्थान या परिसर, ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग से सम्बन्धित बाह्य गृह, यदि कोई हो, और पेट्रोल, डीजल या गैस लाइनें, प्रतिष्ठान या पम्प सम्मिलित हैं ;

(ग) 'भवन उपविधियों' का तात्पर्य किसी सुसंगत नगर पालिका विधि के अधीन बनायी गयीं भवन उपविधियों, नियमों तथा विनियमों से है और इनमें विकास नियंत्रण नियम या विनियम, उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाये, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाये गये कोई अन्य भवन नियम या विनियम सम्मिलित हैं और वे ऐसे क्षेत्र में हों, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो;

(घ) 'भारतीय मानक ब्यूरो' का तात्पर्य भारतीय मानक अधिनियम) 2016, अधिनियम संख्या 11 सन् (2016के अधीन स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय से है ;

(ङ) 'उपविधि' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अधीन बनाए गये अग्निशमन सुरक्षा विनियमों या प्रतिमानों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों, वास्तविक प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित भवन उपविधियों, तेल-उद्योग सुरक्षा निदेशालय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, पेट्रोलियम अधिनियम तथा नियमों, अग्निशमन से सम्बन्धित भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियमों अथवा समय-समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित किन्ही सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धान्तों से है ;

(च) 'निदेशक' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 6के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(छ) 'महानिदेशक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(ज) 'आपदा' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में यथा परिभाषित आपदा से है ;

(झ) 'आपात' का तात्पर्य आपदा सहित किसी ऐसी गम्भीर स्थिति या घटना से है, जो अप्रत्याशित रूप में घटित होती है, जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अग्निशमन तथा आपात सेवा की तत्काल कार्यवाही की मांग होती है;

(ञ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ट) 'वास्तविक प्राधिकरण' में स्थानीय प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर निगम, आवास विकास परिषद या भवन योजना अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण सम्मिलित हैं ;

(ठ) 'परिनिर्माणकर्ता' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-समूह से है, जो नियमित हो, या अन्यथा रूप में हो, जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के व्यवसाय हेतु कोई पण्डाल या कोई संरचना परिनिर्मित करता है, या बनाता है;

(ड) 'अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों' का तात्पर्य इस निमित्त बनायी गयी नियमावली में विहित अग्नि सुरक्षा तंत्र सहित ऐसे उपायों से है, जो अग्नि की परिरुद्धता, नियन्त्रण तथा शमन के लिए और अग्नि की स्थिति में जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार आवश्यक हों ;

(ढ) 'अग्नि सुरक्षा अधिकारी' का तात्पर्य कतिपय परिसरों और भवनों में प्रतिष्ठापित अग्नि रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसे परिसरों और भवनों के स्वामी या अध्यासी द्वारा इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ण) 'अग्निशमन अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय रोपण स्थलों हेतु राज्य द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

(त) 'अग्निशमन केन्द्र' का तात्पर्य अग्निशमन सम्बन्धी उपस्करों ,उपकरणों और कर्मचारिवृन्द को आवासित करने हेतु परिनिर्मित ऐसे किसी भवन से है ,जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अग्निशमन केन्द्र या अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों के रूप में सामान्यतः या विशिष्टतः घोषित हो ;

(थ) 'निधि' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन गठित निधि से है ;

(द) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य किसी नगर पालिका परिषद ,नगर पालिका ,नगर महापालिका ,नोटिफाइड एरिया कमेटी ,टाउन एरिया कमेटी ,जिला परिषद ,छावनी परिषद ,क्षेत्र समिति , ग्राम सभा या स्थानीय स्वशासन के प्रयोजनार्थ गठित किसी अन्य प्राधिकरण या नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन सहित राज्य सरकार के प्रति विधिक रूप से हकदार या उसके द्वारा न्यास कृत ग्राम प्रशासन से है ;

(ध) 'स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(न) 'राष्ट्रीय भवन संहिता' का तात्पर्य भवनों ,स्थानों ,परिसरों ,कार्यशालाओं ,भण्डारगारों तथा उद्योगों में क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से युक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पुस्तक या पुस्तकों से है ;

(प) 'अध्यासन' का तात्पर्य ऐसे प्रमुख अध्यासन से है ,जिसके लिए कोई भवन या भवन का कोई आंशिक भाग प्रयुक्त किया जाता है या उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है जिसमें ऐसे सहायक अध्यासन सम्मिलित हैं ,जो उस पर समाश्रित हैं ;

(फ) 'अध्यासी' का तात्पर्य:-

(एक) ऐसे किसी व्यक्ति से है ,जो तत्समय ऐसी भूमि या भवन ,जिसके सम्बन्ध में किराये का संदाय किया जाता हो /या संदेय हो ,के किराये या उसके आंशिक भाग का संदाय भवन स्वामी को कर रहा हो या संदाय करने का दायी हो ;

(दो) अपनी भूमि या भवन में अध्यासित या उसका अन्य रूप में उपयोग करने वाले किसी स्वामी से है ;

(तीन) किसी भूमि या भवन के निःशुल्क किरायेदार से है ;

(चार) किसी भूमि या भवन के अध्यासित लाइसेंसधारी से है ;और

(पांच) ऐसे किसी व्यक्ति से है ,जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन हेतु भवन स्वामी को क्षतियों का संदाय करने के लिए दायी हो ।

(ब) 'स्वामी' में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है ,जो तत्समय किसी अभिकर्ता ,न्यासी ,संरक्षक या प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया अपने खाता में या अपने तथा अन्य के खाता में प्राप्त करने का हकदार हो अथवा जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए यदि भूमि या भवन या उसका आंशिक भाग ,किरायेदार को किराया पर दिया गया हो ;

(भ) 'पण्डाल' का तात्पर्य ऐसे छत या दीवारों वाले अस्थायी संरचना से है ,जो पुआल ,फूस ,उलू , तृण ,गोलपट्टा ,होगला ,डर्मा ,मैट ,कैनवास ,बखर या ऐसी अन्य समान प्रकार की सामग्री से निर्मित हो ,जो स्थायी या निरन्तर अध्यासन के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है ;

(म) 'द्वितीय अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है ,जो इस अधिनियम की धारा 45में यथा परिभाषित अपील प्राधिकारी से कम से कम एक रैंक उच्चतर हो ;

(य) 'स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद्' का तात्पर्य अग्निशमन सेवा से सम्बन्धित प्राविधिक समस्याओं का परीक्षण करने और भारतीय मानक संस्थाओं के माध्यम से अग्निशमन उपकरणों का मानकीकरण सहित मामलों में भारत सरकार को संस्तुति करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित सलाहकार निकाय से है ;

(र) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ल) 'अर्ह अभिकर्ता' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है ,जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन के क्षेत्र में प्राविधिक विशेषज्ञता हो और जिसके पास अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त विषयगत ज्ञान और उपलब्धियां हों ।

अध्याय—दो

अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा की स्थापना

3-(1) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा होगी और अग्निशमन तथा आपात सेवा के समस्त अधिकारी और अधीनस्थ रैंक के कार्मिक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की किसी शाखा में तैनात किये जाने योग्य होंगे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अग्निशमन दल या किसी अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को यह घोषित कर सकती है कि उक्त दल या सेवा किसी भी समय राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग होगा अथवा नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यह उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग के, स्वामी या अध्यासी द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग हेतु अग्नि सुरक्षा आच्छादन का उपबंध करने के लिए अनुरक्षित निजी अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के निमित्त लागू नहीं होगा।

(2) इस अधिनियम अथवा स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी अग्निशमन दल या अग्नि रोकथाम से सम्बन्धित सेवा को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांकों से राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग घोषित कर सकती है।

(3) अग्नि के फलस्वरूप हुई आपदा से भिन्न किसी आपदा में सहायता करने के उद्देश्य से समस्त अग्नि शमन सेवाएं आपात सेवाएं मानी जायेंगी:

परन्तु यह कि यदि जहाँ आपात सेवा केवल अग्निशमन से संबंधित न हो वहाँ आपात सेवा के प्रभारी प्राधिकारी के विनिश्चय और निदेश अभिभावी होंगे।

अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होना

4-सम्पूर्ण राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण और उस पर नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा, ऐसे अग्निशमन अधिकारियों जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर नियुक्त करे, के माध्यम से इस अधिनियम और/या तद्विना बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जायेगी।

अग्निशमन तथा आपात सेवा का गठन और वर्गीकरण

5-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभिन्न रैंकों के उतनी संख्या में कर्मचारिवृंद होंगे और उसमें ऐसे संगठन होंगे तथा उसकी ऐसी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगे, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार नियमावली में निम्नलिखित को विहित कर सकती है:—

(एक) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के भिन्न-भिन्न पद;

(दो) कर्मचारिवृंद की भर्ती की रीति, पद का ग्रेड, अर्हता, वेतन, भत्ते और उक्त सेवा में विनियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की अन्य सेवा शर्तें।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य में विद्यमान अग्निशमन तथा आपात सेवा की पद्धति की समीक्षा कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो उसे उपान्तरित कर सकती है:

परन्तु यह कि स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु इस उपधारा के अधीन निर्मित नियमावली में कर्मचारिवृंद की भर्ती की रीति, वेतन, भत्ते तथा तत्सम्बन्धी मामले सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) इस अधिनियम द्वारा या तद्विना अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व के दिनांक को किसी प्राधिकरण के विद्यमान अग्निशमन दल या अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के अग्निशमन अधिकारी या कर्मचारिवृंद या कर्मचारी (जिस भी पदनाम से पुकारा जाय (के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा जैसा कि उसके लिए ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे और वह पूर्व की भांति तथा इस अधिनियम द्वारा या तद्विना उन्हें प्रदत्त शक्तियों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

6-(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी को महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के रूप में नियुक्त करेगी, जिसे आगे महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा जायेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हैं और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगी।

(2) राज्य सरकार अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में वास्तविक अर्हता ज्ञान, अनुभव तथा विश्वसनीय उपलब्धियों से युक्त अग्निशमन अधिकारी को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्दीन विनिर्दिष्ट हों।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की सहायता हेतु ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगी, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण, निदेशों तथा अधीक्षण के अधीन महानिदेशक तथा निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय तथा उस पर अधिरोपित किया जाय।

7-(1) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन अग्निसुरक्षा तथा उसकी रोकथाम, अग्निशमन उपस्करों, मशीनरी तथा उपकरणों, प्रशिक्षण, व्यक्ति पर्यवेक्षण, पारस्परिक सम्बन्धों की घटनाओं, कर्तव्य आवंटन, विधि अध्ययन, आदेशों तथा कार्यवाहियों की रीतियों से संबंधित समस्त मामलों और सुसंगत राज्य नियमावली के अनुसार अपने अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा किये जाने तथा उनके मध्य अनुशासन बनाये रखने के कार्यकारी विवरण के समस्त मामलों के लिये निदेश देगा और उनका विनियमन करेगा।

(2) धारा 6की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा,—

(एक) कार्यालय महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

(दो) अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास हेतु राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करेगा;

(तीन) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास के सम्बन्ध में नीतियां निर्मित करेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने हेतु कदम उठायेगा;

(चार) प्राधिकारियों द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपस्कर, अग्निशमन सम्पत्ति और अग्निशमन मानव शक्ति की समय-समय पर समीक्षा के सम्बन्ध में योजनाएं और प्रस्ताव तैयार करेगा और उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा;

(पाँच) प्रचण्ड अग्निकाण्ड, गृह ध्वंस और अन्य आपात सेवाओं के मामलों में प्रभावी कदम उठायेगा या उठावाएगा और उपाय करेगा तथा करवायेगा;

(छः) अग्नि के कारण का अन्वेषण करेगा या अन्वेषण करायेगा और अग्निशमन सम्बन्धी सावधानी के उपायों को क्रियान्वित करने हेतु प्राधिकारियों को परामर्श देगा;

(सात) अग्निशमन सेवा कर्मियों के प्रत्येक स्तर पर विहित कार्यों के अनुसार प्रभावी मानव संसाधन विकास नीतियों को क्रियान्वित करेगा और उक्त प्रयोजनार्थ वह उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकता है;

(आठ) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के मानक का अद्यतनकरण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा;

(नौ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या तद्दीन प्रदत्त, अधिरोपित या आवंटित किया जाय।

8-(1) कतिपय उद्योगों और वृहद वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक अधिष्ठानों एवं भवनों में जनसंख्या तथा संभाव्य अग्नि सम्बन्धी खतरों और उपबंधित एवं अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित अग्निशमन केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द का उपबंध करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार राज्य के भीतर अग्निसुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उतने अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों का सृजन कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1)के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना में अग्निशमन केन्द्रों और उनसे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाएं परिभाषित होंगी और प्रशासनिक तथा संचालनात्मक दक्षता हेतु आवश्यक अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाओं तथा विस्तार को परिनिश्चित किया जायेगा।

महानिदेशक और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की नियुक्ति

महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्ति, कर्तव्य तथा कृत्य

अग्निशमन सेवाओं की स्थापना

अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य

9-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार,—

(क) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा प्राधिकृत अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के एक अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी होगा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अग्निशमन सेवा के आकार के अनुसार अग्निशमन केन्द्र का प्रभार धारण करेगा ;

(ख) उसके पास अग्निशमन केन्द्र से उसके अधीन सम्बद्ध ऐसे कर्मचारिवृन्द होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ;

(ग) वह अपने अग्निशमन केन्द्र के क्षेत्रों के भीतर संचार प्रणाली हार्डवेयर सहित जल संसाधनों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा संचालन का प्रभारी होगा ;

(घ) अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों, यदि कोई हों, हेतु समान व्यवस्थाओं का उपबन्ध किया जा सकता है।

अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य—

(2) अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे:—

(क) महानिदेशक के नियंत्रण, निदेश तथा अधीक्षण के अधीन अधिनियम की इस धारा की उपधारा) 1 (के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसाकि उसे इस अधिनियम या तद्वीन बनायी गयी नियमावली द्वारा प्रदत्त तथा अधिरोपित किये जाय ;

(ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अग्निशमन रोकथाम तथा आपदा के मामले में इस धारा की उपधारा) 1 (के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी या अधिकारीगण अपनी अधिकारिता के निमित्त किसी अग्नि या आपात स्थिति में उस घटना हेतु अन्य अग्निशमन कार्य तथा आपात सेवा में विनियोजित व्यक्ति उसके अधीन कार्य करेंगे।

अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य

10-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार प्रशासनिक प्रयोजनों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थल हेतु समय-समय पर यथा-आवश्यक अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, अर्हताएं और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि नियमावली में विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्वीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अबाध रूप से शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान अग्निशमन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने हेतु ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

11-(1) अग्निशमन तथा आपात सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा और तदोपरान्त ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी की शक्तियाँ, कृत्य और विशेषाधिकार होंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा का कर्मचारी होने से किसी कारणवश प्रविरत हो जायेगा, और ऐसा कर्मचारी होने से उसके प्रविरत होने पर उसे तत्काल उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी को उक्त प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करना होगा।

(3) कोई नियुक्ति प्रमाण-पत्र अकृत हो जायेगा, जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से प्रविरत हो जायेगा और उक्त अवधि के दौरान वह अक्रियाशील रहेगा और ऐसा व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से निलम्बित कर दिया जायेगा।

(4) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी अपनी सेवा की निबन्धन एवं शर्तों और अन्य समस्त सम्बन्धित मामलों में ऐसी नियमावली से शासित होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू हो।

सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा

12- जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्निशमन तथा आपात सेवा में वृद्धि किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्र हेतु तथा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह नियमावली के अनुसार उचित समझे, स्वयं सेवकों का नामांकन करके सहायक सेवा में वृद्धि कर सकती है।

अग्निशमन अधिकारी के निलम्बन का प्रभाव

13- किसी अग्निशमन अधिकारी में निहित शक्तियाँ, कृत्य तथा विशेषाधिकार तब तक निलम्बित रहेंगे जब तक ऐसा अग्निशमन अधिकारी निलम्बनाधीन रहेगा :

परन्तु यह कि ऐसे निलम्बन के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति उन्ही प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन रहेगा, जिसके अधीन वह रहता, यदि वह निलम्बनाधीन न होता।

अध्याय-तीन

अग्निशमन तथा आपातकालीन सहयोग

14- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, नियमावली में विहित मानक संचालनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार समस्त अग्निशमन तथा आपात से सम्बंधित पुकारों के लिए सहयोग करेगा। किन्हीं अन्य आपातों से सम्बंधित पुकारों को भी आदेश द्वारा तथा नियमावली के अनुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

पुकारे जाने पर सहयोग

15 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट किसी अग्नि दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान तात्कालिक कर्तव्यों के निमित्त अग्निशमन तथा आपात सेवा संसाधनों, उपस्करों तथा अग्निशमन कर्मियों को अभिनियोजित करना होगा।

कार्मिक और उपस्करों का पैमाना

16 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को कर्मचारिवृंद के नियोजन, आयोजन तथा अभियोजन का विवरण उपलब्ध कराना होगा और नियमावली के अनुसार नियमित स्थलीय अनुश्रवण सुनिश्चित करना होगा।

संचालनात्मक प्रबंधन

17 - किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, में अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई भी सदस्य, जो मौके पर अग्निशमन प्रचालनों का प्रभारी हो,—

अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शक्तियाँ

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को हटा सकता है, या उसे हटाने के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अन्य सदस्य को आदेश दे सकता है जो अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति को बचाने हेतु कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता हो या उसमें व्यवधान डालता हो;

(ख) ऐसे किसी सड़क या मार्ग को बंद कर सकता है जिस पर या जिसके निकट अग्नि बुझाई जा रही हो और/या बचाव कार्य प्रगति पर हो;

(ग) अग्नि बुझाने और बचाव कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ तथा अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ यथा सम्भव कम से कम क्षति पहुँचाते हुए हौज या उपकरण मार्ग बनाने हेतु किसी परिसर या उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है या उन्हे गिरवा सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे/किसी परिसर के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को हुई क्षति की सीमा तक युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान नियमावली में यथा विहित रीति से किया जायेगा;

(घ) क्षेत्र के जलापूर्ति प्रभारी प्राधिकारी से मुख्य जल स्रोतों को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि अग्नि लगने वाले स्थान पर विनिर्दिष्ट दबाव के साथ जलापूर्ति की जा सके और ऐसी अग्नि को बुझाने या फैलने से रोकने तथा बचाव कार्य संचालनों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ किसी झरना, सिस्टर्न, कुआँ या तालाब अथवा सार्वजनिक या निजी उपलब्ध किसी जल स्रोत से जल का उपयोग कर सकता है;

(ङ) अग्नि कार्य संचालनों में संभाव्य रूप में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति-समूह को तितर-बितर करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानों वह किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी हो और मानो ऐसी भीड़ अविधिमान्य भीड़ हो और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के संदर्भ में ऐसे अधिकारी के रूप में उसी प्रतिरक्षा तथा संरक्षण हेतु हकदार होगा;

(च) अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में लगे अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मियों के लिए जानबूझ कर व्यवधान डालने तथा बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और समय, दिनांक तथा गिरफ्तारी का कारण उल्लिखित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी सहित अविलम्ब उसे किसी पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाना पर सौंप सकता है;

(छ) किसी क्षेत्र में लगने वाली आग से निपटने के प्रयोजनार्थ यथाविहित निबंधनों पर सुनिश्चित करने हेतु अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ दोनों कर्मियों या उपकरणों को नियोजित तथा अनुरक्षित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकता है;

(ज) अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का संरक्षण या दोनों करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों।

अध्याय—चार

जल आपूर्ति

आपात के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति

18 - अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों के दौरान और अपेक्षित अवसरों पर ऐसे क्षेत्र में किसी जल स्रोत, जिसे वह आवश्यक समझे, से जल निकालना निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन कार्य संचालनों के अग्निशमन अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा और प्राधिकारी या स्वामी या ऐसे जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले अध्यासी को उस प्रयोजनार्थ यथा विहित दरों पर जल आपूर्ति करनी होगी।

जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का कर्तव्य

19 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नि की समस्त युक्तियुक्त स्थिति में नियमावली के अनुसार उपयोग हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध होगी, समस्त युक्तियुक्त उपाय करने होंगे।

जल आपूर्ति के लिए करार करने की शक्ति

20 - निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी नियमावली में विहित तृतीय पक्षकार को संदाय करने हेतु प्रक्रियाओं तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जलापूर्ति की मांग और जल की आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिये किसी अभिकरण के साथ करार कर सकता है।

जल आपूर्ति बाधित होने पर किसी प्रकार का न होना

21 - किसी क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रभारी प्राधिकारी धारा 17 के खण्ड) घ (के अनुपालन में हुए किसी प्रकार की जल आपूर्ति व्यवधान के कारण क्षति हेतु प्रतिकर के लिए कोई दावा करने का दायी नहीं होगा।

जल का प्रतिकर

22 - अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों में उपभोग किये गये जल हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रभार ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अध्याय—पाँच

अग्नि तथा आपात रोकथाम हेतु सामान्य उपाय और जीवन सुरक्षा के उपाय

रोकथाम संबंधी उपाय

23-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के प्रयुक्त परिसरों या किसी श्रेणी के परिसरों, जिनसे उसकी राय में अग्नि का खतरा होना सम्भाव्य हो, के स्वामी या अध्यासी से ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है।

(2) जहाँ ऐसी अधिसूचना जारी की गयी हो वहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अग्नि लगने की सम्भावित खतरों वाली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और ऐसा करने के लिए स्वामी या अध्यासी के विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अध्यासी को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकता है, निरूद्ध कर सकता है या हटा सकता है।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की अग्निशमन तथा आपात प्रबंधन योजनायें, संबन्धित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

पंढालों में अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का स्व विनियामक होना

24- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 23 के अधीन विहित अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपाय करने हेतु पण्डाल परिनिर्मित किया जाना स्व विनियामक समझा जायेगा।

(2) पण्डाल परिनिर्माणकर्ता को पण्डाल के प्रमुख स्थान पर विहित प्रपत्र में और अपने हस्ताक्षर से इस आशय की घोषणा प्रदर्शित करनी होगी कि उसने उसमें राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समस्त विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को ग्रहण किया है।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपधारा (2) के अधीन परिनिर्माणकर्ता द्वारा कृत घोषणा की सत्यता को सत्यापित करने और विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के निदेश के साथ त्रुटियाँ, यदि कोई हों, इंगित करने की दृष्टि से पण्डाल में प्रवेश करे और निरीक्षण करे। यदि इस प्रकार दिये गये समय के भीतर निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी उक्त पण्डाल को सीलबंद कर देगा।

(4) किसी पण्डाल परिनिर्माणकर्ता, जो यह मिथ्या घोषणा करता है कि उसने पण्डाल में विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है, को इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

25-(1) जहाँ धारा 23 तथा धारा 24 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो वहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिये यह विधिमान्य होगा कि वह अतिक्रमणों या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या अग्नि बुझाने में किसी प्रकार के व्यवधान को किसी सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिये निदेश दे और यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को ऐसा करने में विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त मामले का न्याय निर्णयन करने का अनुरोध करते हुए उक्त मामले की रिपोर्ट उस उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में परिसर या भवन या पंडाल स्थित हो:

परन्तु यह कि जहाँ निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को अग्नि लगने का आसन्न खतरा या अग्नि बुझाने हेतु व्यवधान मानता हो वहाँ वह ऐसे परिसर या भवन के स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को अतिक्रमण या वस्तुओं या सामानों को तत्काल हटाने के लिये निदेश दे सकता है और तदनुसार उक्त मामले की रिपोर्ट उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट ऐसी रीति, जैसा कि वह उचित समझे, से तामील की गयी नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या सामानों या अग्नि बुझाने में व्यवधान को हटाये जाने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उप जिला मजिस्ट्रेट विहित नियमावली के अनुसार ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने का आदेश दे सकता है।

(4) उपधारा (3) में कृत आदेश के निष्पादन हेतु प्रभारित व्यक्ति तत्काल उन वस्तुओं तथा सामानों की सूची उसी समय तैयार करेगा जिन्हें वह ऐसे आदेश से जब्त करेगा और जब्ती के समय उक्त वस्तुओं के कब्जाधीन व्यक्ति को इस निमित्त विहित रीति से एक लिखित नोटिस देगा कि उसमें उल्लिखित उक्त वस्तुओं या सामानों का विक्रय कर दिया जायेगा, यदि उन वस्तुओं का दावा उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गयी नोटिस के अनुसरण में जब्त की गयी वस्तुओं का दावा करने में ऐसे व्यक्ति, जिसके कब्जाधीन उक्त वस्तुएं व सामान कब्जा के समय थे, के विफल होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार सार्वजनिक निलामी द्वारा उन वस्तुओं को विक्रीत कर देगा।

26-(1) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता पृथक-पृथक वास्तविक प्राधिकरणों की उपविधियों, किसी अन्य विधि या उपविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमावली द्वारा बर्गीकृत भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी या अध्यासी, जो वैयक्तिक या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हों, को उसमें अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपायों का उपबंध करना होगा :

परन्तु यह कि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को,—

(एक) उपविधियों में यथा उपबंधित न्यूनतम अग्नि बुझाने और जीवन सुरक्षा प्रतिष्ठापनों का उपबंध करना होगा;

(दो) अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट रीति और विशिष्टताओं के अनुसार सदैव सक्रिय स्थिति में अनुरक्षित रखना होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यासन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सशक्त कोई प्राधिकारी उक्त प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्वामी या अध्यासी ने वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से इस धारा की उपधारा(1) में दिये गए उपबंध का अनुपालन कर लिया है।

(3) लागू विद्यमान भवन उप विधियों और राज्य द्वारा उपविधियों के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित भवनों को अग्निशमन तथा आपात सेवा से "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र "प्राप्त करना होगा,—

(एक) 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले बहुमंजिले भवन;

(दो) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 में यथा परिभाषित विशेष भवन यथा शैक्षिक, संस्थागत सभागत, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण संबंधी तथा खतरनाक भवन,—

(तीन) 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले पूर्वोक्त किसी अध्यासन के साथ मिश्रित अध्यासन।

(4) उपधारा (3) के अधीन भवन स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बहुमंजिले या विशिष्ट भवनों में विहित नियमावली के अनुसार अग्नि रोकथाम या उसे बुझाने हेतु अग्नि रोकथाम, अग्निशमन तथा जीवन सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा तंत्र लगाया जाय ;

(5) यथास्थित स्वामी या अध्यासी को अग्निशमन अधिकारी का इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा तद्दीन यथा अपेक्षित अपने भवन या उसके आंशिक भाग में अग्निरोकथाम, अग्निशमन तथा जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के संबंध में किसी अर्ह अभिकरण द्वारा जारी विहित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस धारा की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अर्ह मरम्मत युक्त तथा पर्याप्त स्थिति में अग्निरोकथाम तंत्र के अनुरक्षण के सम्बन्ध में वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई माह में विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी को भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट अर्ह अभिकर्ताओं से भिन्न व्यक्ति, अग्निरोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का कार्य नहीं करेगा अथवा किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में करने हेतु अपेक्षित ऐसे अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों का निष्पादन नहीं करेगा।

अग्नि लगने के सम्भावित खतरा वाले या अग्नि बुझाने में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों का हटाया जाना

अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का स्वामी या अध्यासियों का उत्तरदायित्व

अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र
जारी किया जाना

27-(1) अग्निशमन अधिकारी को यथास्थिति स्वामियों या अध्यासियों या आवेदकों द्वारा स्वतन्त्र रूप से या संयुक्त रूप से कृत धारा 26 की अपेक्षाओं के संबंध में अनुपालनों की संवीक्षा करनी होगी और आवश्यक जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् इस शर्त के अधीन आवेदन करने के एक माह के भीतर अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना होगा कि समस्त आवश्यक दस्तावेज, अभिकल्प, मानचित्र तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि स्वामी, अध्यासी या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) यदि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी, अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन जारी अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र, स्वामी या अध्यासी को कारण बताओ की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा।

(3) भवन या परिसर का स्वामी या अध्यासी, जिसका अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र उसकी ओर से कृत त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया हो, इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किये जाने के आधार पर भवन या परिसर में अध्यासित होने का हकदार नहीं होगा।

(4) कोई व्यक्ति ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग में स्थापित किसी अग्नि रोकथाम तथा सुरक्षा उपकरण से छेड़ छड़ा नहीं करेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, उसे नहीं हटाएगा या उसे क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या उसका नुकसान नहीं करेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने हेतु दुष्प्रेरित नहीं करेगा।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी की
नियुक्ति तथा कृत्य

28-(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कारखाना या भवन या परिसर के प्रभावी अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्वामी और अध्यासी या अध्यासीगण को यथास्थिति वैयक्तिक या संयुक्त रूप में,—

(एक) यथा विहित अर्हताओं वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ;

(दो) अग्निशमन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी।

(2) उपधारा (1)के अधीन इस प्रकार नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी को विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहरबंद नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(3) उपधारा (1)के अधीन नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी पद की, त्याग-पत्र के आधार पर या अन्यथा रूप में, रिक्ति होने की स्थिति में स्वामी या अध्यासी या अध्यासीगण से यथास्थिति वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से तत्काल अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) उपधारा (1)में यथा उल्लिखित अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में अग्निशमन अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे जिसके अन्तर्गत कारखाना बंद करने हेतु श्रमायुक्त को और अन्य मामले में सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु सुसंगत प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाना सम्मिलित है।

(5) अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसाकि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय :

परन्तु यह कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्ति से अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

29 - (1) अग्निशमन अधिकारी ,अध्यासी को या यदि कोई अध्यासी न हो तो किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी को तीन घण्टे की नोटिस देने के पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय ऐसे स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में प्रवेश अथवा निरीक्षण कर सकता है ,जहाँ अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उल्लंघन को अभिनिश्चित करने हेतु ऐसा निरीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो:

निरीक्षण की शक्ति

परन्तु यह कि अग्निशमन अधिकारी ऐसे किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है ,यदि ऐसे स्थान ,भवन या उसके आंशिक भाग पर कोई क्रियाशील हो या कोई मनोरंजन चल रहा हो अथवा यदि उसे जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो।

(2) अग्निशमन अधिकारी को उपधारा (1)के अधीन निरीक्षण करने हेतु उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वामी या अध्यासी या कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सशक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश के लिए व्यवधान नहीं डालेगा या व्यवधान नहीं डालने देगा अथवा निरीक्षणार्थ इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा।

(4) जब मानव निवास हेतु प्रयुक्त उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में उपधारा (3)के अधीन प्रवेश किया जाय तब अध्यासियों के सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं के लिए सम्यक सम्मान प्रदान किया जायेगा और उपधारा (3)के अधीन किसी ऐसी महिला ,जो सार्वजनिक रूप से प्रकट न होती हो ,के किसी फ्लैट ,अपार्टमेंट या ऐसे भवन के आंशिक भाग में प्रवेश करने से पूर्व उसे नोटिस प्रदान की जायेगी कि वह वहां से निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे निकलने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा प्रदान की जायेगी।

(5) जहाँ इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन निरीक्षण ,अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जाये ,वहां उसे सम्बन्धित वास्तविक प्राधिकारी को ऐसे किसी निरीक्षण की रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।

(6) अग्निशमन अधिकारी को इस धारा के अधीन उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् उक्त भवन की ऊंचाई या उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में की जाने वाली क्रिया-कलापों की प्रकृति के सन्दर्भ में उनमें उपबन्धित की जाने वाली अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों अथवा ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या उनका अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित अपेक्षाओं से विचलन या उनका उल्लंघन किये जाने पर अपना दृष्टिकोण अभिलिखित करना होगा और ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग को स्वामी या अध्यासी को एक नोटिस ,उसमें यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत उपायों को ग्रहण करने हेतु उसे निर्देशित करते हुए ,जारी करना होगा।

30 - अग्नि लगने से सम्बन्धित कोई सूचना धारण करने वाले किसी व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम अग्निशमन केन्द्र पर तत्सम्बन्ध में सूचना देनी होगी।

अग्नि लगने की सूचना

अध्याय-छः

अपराध और शास्तियाँ

31- जो कोई अध्याय-चार के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह इस अधिनियम और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की गयी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास ,जो छः माह तक हो सकता है ,से या ऐसा जुर्माना ,जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनों से दण्डनीय होगा और जहाँ अपराध जारी रहेगा वहां एक अग्रतर जुर्माना ,जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम अपराध के पश्चात् प्रतिदिन तीन हजार रुपये तक हो सकता है ,के साथ दण्डनीय होगा।

अध्याय-चार जल आपूर्ति उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ

32- ऐसी किसी कार्यवाही ,जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकती है ,के होते हुए भी ,अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई सदस्य ,जो,—

कर्तव्य उल्लंघन के लिए शास्ति

(एक) कर्तव्य के किसी उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का जानबूझ कर उल्लंघन करने का दोषी पाया जायेगा ;या

(दो) कायरता का दोषी पाया जायेगा ;या

(तीन) पन्द्रह दिनों या उससे अधिक के लिए अनुज्ञा या पूर्व सूचना दिए बिना अपने कार्यालय के कर्तव्यों से प्रत्याहृत रहेगा या प्रविरत रहेगा ;या

(चार) अवकाश पर अनुपस्थित होने के कारण युक्तियुक्त कारण के बिना उक्त अवकाश की समाप्ति पर स्वयं ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने में विफल रहेगा ;या

(पाँच) कोई अन्य नियोजन या पद ग्रहण करेगा या उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली , 1956के उपबंधों का उल्लंघन कर कारोबार में स्वयं को अभिनियोजित करेगा ;

ऐसे कारावास ,जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना ,जो तीन माह के वेतन से अनधिक धनराशि तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में शास्ति

33-(1) यदि किसी भवन या परिसर का कोई स्वामी या अध्यासी या ऐसे स्वामियों और अध्यासियों का संघ, धारा 28 के अधीन अग्निसुरक्षा अधिकारियों की इस निमित्त यथास्थिति निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दोषी माना जायेगा।

(2) जब ऐसे अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषी माना जाए तब निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा अवधारित परिसर स्थित सामान्य क्षेत्रों सहित उसके द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अध्यासन प्राप्त कुल निर्मित क्षेत्र के अन्यून दस रुपये प्रति वर्ग मीटर और अनधिक पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर की धनराशि, उसमें प्रत्येक माह की वृद्धि या उसके आंशिक भाग के लिए शास्ति के माध्यम से वसूल की जायेगी।

(3) उपधारा (2)के अधीन जुर्माना स्वरूप धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

प्रतिकर का संदाय करने के लिए संपत्ति स्वामी का दायित्व

34-(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति में, उसकी स्वयं की या उसके अभिकर्ता की जानबूझकर या लापरवाही पूर्ण कृत कार्यवाही के कारण अग्नि लग जाती है, इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन उसमें उल्लिखित किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण अपनी सम्पत्ति की क्षति के भुक्तभोगी किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1)के अधीन समस्त दावे, क्षति होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करेगा और ऐसी धनराशि तथा तद् निमित्त उत्तरदायी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा, और इस प्रकार पारित आदेश में धारा 45में यथा उल्लिखित तीस दिनों के भीतर किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रवर्तन निहित होगा।

सूचना देने में विफलता

35-ऐसे किसी व्यक्ति, जो पर्याप्त औचित्य के बिना, अग्नि लगने के संबंध में अपने पास स्थित सूचना संसूचित करने में विफल रहता है, को भारतीय दंड संहिता 1860, (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ माना जाएगा।

सावधानी बरतने में विफलता

36-जो कोई व्यक्ति/युक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा या उक्त धारा के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है, वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात्, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, प्रतिदिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में जानबूझकर व्यवधान डालने के लिए शास्ति

37-ऐसा कोई व्यक्ति, जो अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य, जो अग्नि बुझाने संबंधी कार्य संचालनों में अभी नियोजित हो, के लिए जानबूझकर व्यवधान डालता हो या बाधा उत्पन्न करता हो, ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दंडनीय होगा।

मिथ्या रिपोर्ट

38-ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर किसी कथन, संदेश या अन्यथा के माध्यम से अग्नि लगने की मिथ्या रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान करता है या प्रदान करवाता है, ऐसे कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है से या, दोनों से दंडनीय होगा।

अपराध हेतु दंड के सामान्य उपबंध

39-जो कोई इस अधिनियम या तद्वीन बनायी गयी किसी नियमावली या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम और तद्वीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपने विरुद्ध कृत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना, जो प्रथम अपराध के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।

40-(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी रहा हो या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, साथ ही साथ कंपनी भी, अपराध के दोषी माने जाएंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने तथा तदनुसार दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दंड के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किए जाने से रोकने के लिए समस्त सम्यक परिश्रम किया था ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि उक्त अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या वह उसकी ओर से कृत किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दंडित किए जाने का दायी होगा ;

स्पष्टीकरण: -इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) 'कंपनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम सम्मिलित है ; और

(दो) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

41- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् कृत किसी अपराध, जो इस अधिनियम की धारा 363, 73, 83, 9, या तद्दीन बनायी गई किसी नियमावली के अधीन दंडनीय हो, का प्रशमन, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारियों द्वारा ऐसी धनराशि के स्थान पर जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकता है :

परंतु यह कि ऐसा कोई अपराध प्रशमनीय नहीं होगा, जो राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से जारी नोटिस, आदेश या अध्यापेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण किया गया हो और जब तक उसका अनुपालन न किया गया हो, जहां तक अनुपालन संभव हो ।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहां यदि अपराधी अभिरक्षा में हो तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अग्रतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी ।

42- इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गई किसी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

43- कोई न्यायालय, निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत या उससे प्राप्त सूचना के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की कार्यवाही नहीं करेगा ।

44- न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करेगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध

अपराधों का प्रशमन किया जाना

सद्भावपूर्वक कृत कार्रवाई का संरक्षण

अभियोजन का संज्ञान

अधिकारिता

अध्याय-सात

अपीलें

45-(1) इस अधिनियम के अधीन जारी या कृत उप जिला मजिस्ट्रेट या अग्निशमन अधिकारी या निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी नोटिस या आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपीलीय अधिकारी को नोटिस या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :

परंतु यह कि अपीलीय अधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी को अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ विरोध में की गयी अपील की नोटिस या आदेश की प्रति और इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होंगे ।

(3) किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा ।

अपीलें

अध्याय—आठ

प्रशिक्षण

अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

46- (1) राज्य सरकार राज्य में अग्नि रोकथाम तथा शमन संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रमों का उपबंध करने के लिए एक या उससे अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है और ऐसे किसी केंद्र को बंद या पुनः स्थापित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन स्थापित की जाने वाली अकादमी में स्थानीय निकायों और औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रणाधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए और साथ ही साथ यथाविहित प्रभारों का संदाय किए जाने पर अन्य राज्यों के राजकीय अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार कर सकती है।

(3) राज्य सरकार अग्नि रोकथाम और उसे बुझाने संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रम का उपबंध करने के लिए ऐसी फीस और ऐसी प्रक्रिया विहित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

(4) शिक्षण के संबंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू सामान्य नियमों के अनुपालन के अध्यधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रबंधन के निमित्त राज्य सरकार के लागत और व्यय पर भारत के भीतर और बाहर किसी संस्थान में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की वैज्ञानिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में और अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

सामुदायिक तैयारी

47 - (1) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन तथा अन्य आपात स्थितियों में रोकथाम संबंधी उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा।

(2) अग्निशमन तथा आपात सेवा के नियमों के अनुसार अग्नि रोकथाम से संबंधित मामलों में समुदायों को सहायता और परामर्श प्रदान करेगी।

अध्याय—नौ

अग्निशमन कर, फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण

48-(1) ऐसी किन्हीं भूमियों तथा भवनों पर अग्निशमन कर उद्ग्रहीत किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त वाले क्षेत्रों में स्थित हो, जिन पर संपत्ति कर जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए उस क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहीत किया जाता है।

(2) अग्निशमन कर, संपत्ति-कर पर अधिकार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में ऐसी दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अवधारित करे।

(3) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन लोक प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रणाधीन या कब्जाधीन किसी भवन पर कोई शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।

अग्निशमन कर के निर्धारण, संग्रहण आदि की रीति

49-(1) संपत्तिकर संदाय का निर्धारण करने, संग्रहण करने और प्रवर्तन करने के लिए सशक्त प्राधिकारी राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम के अध्यधीन बनाई गयी, किसी नियमावली के अधीन ऐसा कर उद्ग्रहीत करने हेतु क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को प्राधिकृत करने वाले विधि के अधीन कर संदाय का निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन उसी रीति से करेंगे, जैसा कि संपत्ति कर का निर्धारण, संदाय और संग्रहण किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ वह पूर्वोक्त विधि के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और विवरणी, अपील, समीक्षा, संदर्भ और शास्तिओं से संबंधित उपबन्धों सहित ऐसी विधि के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) अग्निशमन कर के कुल आगमों के ऐसे भाग, जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, की कटौती अग्निशमन कर संग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन संग्रहीत अग्निशमन कर के आगमो का संदाय, उनमें संग्रहण लागत से कटौती करके राज्य सरकार को ऐसी रीति से और ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा को अभिनियोजित किए जाने पर फीस

50-(1) जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर ऐसी सीमाओं के निकट अग्नि बुझाने के उद्देश्य से भेजे जाएं, वहाँ राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विहित किया जाए ;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा मांग की नोटिस तामील किए जाने के एक माह के भीतर संदेय होगी और यदि उक्त अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

देवों की वसूली

51 - इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि की वसूली, भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

अध्याय—दस

अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि

52-(1) अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि "के रूप में ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीस, कर और शास्तियों)जुमाने से भिन्न (के आगमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक रूप से कृत विनियोजन से तथा तद्दीन संग्रहण और वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात् उपधारा (1)के अधीन गठित निधि में प्रविष्ट कर अन्तरित कर दिया जाएगा।

(3) उप-धारा (2)के अधीन निधि में अन्तरित कोई धनराशि राज्य की संचित निधि से वसूल की जाएगी।

(4) निधि की धनराशि का व्यय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित हो।

(5) निधि को संबंधित प्राधिकरण के आय-व्ययक प्राङ्गलन में दर्शाया जाएगा और तत्सम्बंधी खातों का अनुरक्षण तथा लेखा-परीक्षण सुसंगत विधि या तद्दीन बनायी गयी नियमावली और आदेशों, जो संबंधित प्राधिकरण के लिए लागू हों, पर खातों को अनुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त निधि का उपयोग नियमावली में यथाविहित सामुदायिक तैयारी, अवसंरचना प्रशिक्षण और अग्निशमन उपकरणों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा।

अध्याय—ग्यारह

प्रकीर्ण

53 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोक हित में पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या तद्दीन उपबंधित निबंधनों पर अग्निशमन के प्रयोजनार्थ कार्मिकों या उपस्करों या दोनों का उपबंध करने के लिए ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा या प्राधिकरण, जो उक्त अग्निशमन तथा आपात सेवा को अनुरक्षित करता हो, के साथ करार कर सकता है।

अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्था

54 - किसी विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा घोषित कर सकती है।

अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा के रूप में घोषणा अन्य क्षेत्र में अभिनियोजन

55 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, किसी निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त न हो, में अग्नि या अन्य आपात अवसर पर ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र में अग्निशमन सम्बंधी कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों सहित अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को भेजने का आदेश दे सकता है और तदोपरान्त इस अधिनियम तथा तद्दीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंध, समय-समय पर यथाविहित प्रभारों के आधार पर अग्नि सम्बंधी आपात के दौरान या ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि निदेशक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

56 - राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी बचाव, उद्धारण या अन्य कार्यों, जिस निमित्त वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करों के कारण उपयुक्त हो, में अग्निशमन तथा आपात सेवा को नियोजित करे।

अन्य कर्तव्यों पर नियोजन

57 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों से इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति की प्रकृति, उपलब्ध जलापूर्तियों, उनके प्रति पहुँच के साधनों और किन्ही अन्य सारभूत विवरणों के सम्बंध में सूचना प्रदान करने हेतु भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकते हैं और ऐसे स्वामी या अध्यासी को सम्पूर्ण सूचना अपने पास रखनी होगी।

सूचना प्राप्त करने की शक्ति

भवनों या परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति

58-(1) जहाँ धारा 29 के अधीन अग्निशमन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या स्व-प्रेरणा से महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह प्रतीत होता हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है वहाँ वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अध्यासन में ऐसा भवन या परिसर हो, ऐसे भवन या परिसर से तत्काल हट जाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता वाले किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को भवन या परिसर से हटाने के लिये निदेश दे सकता है और ऐसे अधिकारी को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात् महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, भवन या परिसर को सील बंद कर देगा।

(4) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश के सिवाय कोई व्यक्ति उक्त सील को नहीं हटाएगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाओं द्वारा कृत आदेश के अधीन के सिवाय ऐसी मुहर को हटाता है, ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डनीय होगा।

सहायता हेतु पुलिस अधिकारी और अन्य कार्मिक

59 - आग बुझाने सम्बंधी कार्य संचालनों या अग्नि के जोखिम से अर्न्तग्रस्त किसी सामान को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने से संबंधित किन्हीं अन्य कर्तव्यों में पुलिस अधिकारी या पुलिसबल एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करने में निदेशक या ऐसे अग्निशमन अधिकारी की सहायता करें।

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन तथा आपात सेवा को इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन एवं आपात सेवा माना जाना

60 - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—
(एक) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन एवं आपात सेवा (जिसे इस धारा में आगे विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा गया है (इस प्रकार प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन तथा आपात सेवा समझी जाएगी और पद धारण करने वाले विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रत्येक सदस्य को पद धारण करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया तथा पद धारण करने वाला समझा जाएगा।

(दो) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियाँ, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त माने गये पद धारक की हैसियत से उसके समक्ष लम्बित कार्यवाहियाँ मानी जायेंगी और उन कार्यवाहियों को तदनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य की मृत्यु

61 - अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य (राजपत्रित अधिकारी से भिन्न (की कर्तव्यरत रहने के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, राज्य सरकार दाह संस्कार के व्यय स्वरूप सगे नातेदार को समुचित धनराशि या ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे, का भुगतान करेगी।

अधिकारियों का लोक सेवक होना

62 - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत अग्निशमन तथा आपात सेवा का प्रत्येक कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता) 1860, अधिनियम संख्या 45 सन् (1880) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

विवरणी, रिपोर्ट, कथन आदि की मांग

63 - राज्य सरकार महानिदेशक, निदेशक, अग्निशमन अधिकारियों एवं कार्य संचालनात्मक कर्मचारियों और अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारियों से अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनुरक्षण तथा कर्तव्य निष्पादन से सम्बंधित किसी विषय पर विवरणी, रिपोर्ट तथा कथनों की मांग कर सकता है और उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

64-(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकते हैं:-

(क) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की भर्ती, वेतन व भत्ते और सेवा की अन्य समस्त शर्तें ;

(ख) अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं का गठन ;

(ग) नियुक्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र और अग्निशमन अधिकारी जिसकी मुहर के अधीन ऐसा नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ;

(घ) अग्निशमन कर के संदाय के निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन की रीति ;

(ङ) ऐसी रीति, जिसमें संगृहीत अग्निशमन कर का संदाय राज्य सरकार को किया जाएगा ;

(च) अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिए राज्य निबंधनों की सीमाओं के बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा के अभिनियोजन पर फीस ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय, घोषणापत्र, अपील, नोटिस और फीस के न्यूनतम मानक ;

(ज) अग्निशमन तथा आपात सेवा अकादमी पर अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुल्क ;

(झ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारी और अपराधों के प्रशमन के लिए धनराशि ;

(ञ) अग्निशमन तथा आपात सेवा को ऐसे उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना जैसा कि वह उचित समझे ;

(ट) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति कि यह उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा;

(ठ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों और उनके अग्निशमन उपकरणों को समायोजित करने के लिए अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण करना या उनका उपबंध करना या स्थानों को किराये पर लेना;

(ड) आग लगने की सूचना दे चुके और आग लगने के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु प्रभावी सेवा प्रदान कर चुके व्यक्तियों को पुरस्कार देना;

(ढ) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सदाचरण ;

(ण) आग लगने की किसी चेतावनी के अवसर पर आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों के साथ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शीघ्र उपस्थिति सुनिश्चित कराना ;

(त) महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्तियों ,कर्तव्यों और कृत्यों को विनियमित और नियंत्रित करना ;

(थ) सामान्यतः अग्नि तथा आपात सेवा के अनुरक्षण के लिए यथोचित दक्षता की स्थिति बनाये रखना;

(द) पंढालों और अस्थाई संरचना की स्थापना को विनियमित करना ;

(ध) अग्निशमन अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखना ;

(न) अग्निशमन का विवरण और उसकी गुणवत्ता एवं अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों सहित बचाव उपस्कर ,वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अवधारित करना ;

(प) नीतिगत प्रशासन से सम्बंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा निधि का संस्थापन, प्रबंधन और विनियमन ;

(फ) समस्त रैंक और ग्रेड के अग्निशमन अधिकारियों के लिये कर्तव्य समनुदेशित करना और ऐसी रीति विहित करना जिसमें और ऐसी शर्तें विहित करना जिसके अध्यक्षीन वे अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे;

(ब) सामान्यतः अग्निशमन तथा आपात सेवा दक्षता पूर्वक करने और उनके कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा को रोकने के प्रयोजन के लिए;

(भ) न्यूनतम अर्हता ,वास्तविक ज्ञान और अर्ह अभिकरण का अनुभव ;तथा

(म) कोई अन्य मामला जो नियमावली द्वारा अपेक्षित हो या उपबंधित किया जा सकता है ।

शक्तियों का
प्रतिनिधायन

65- (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों, के अधीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

(2) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम द्वारा या तद्विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग और उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का निष्पादन भी आदेश में विनिर्दिष्ट अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति

66 - (1) यू0पी0 अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944, उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा (राजपत्रित अधिकारी (सेवा नियमावली), 2016, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारी सेवा नियमावली 2016, और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु यह कि ऐसे निरसन को किसी स्थानीय प्राधिकरण के सामान्य उत्तरदायित्व को निम्नलिखित के लिए सीमित करना, उपांतरित करना या अल्प करना नहीं समझा जायेगा -

(एक) अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ ऐसी जलापूर्ति तथा अग्नि हाइड्रेंट्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाए, का उपबंध करना और उन्हें अनुरक्षित रखना;

(दो) खतरनाक व्यापारों का विनियमन करने हेतु उपविधियां बनाना;

(तीन) अपने किसी कर्मचारी को अग्नि बुझाने में सहायता करने हेतु आदेश देना, जब अग्निशमन सेवा के किसी सदस्य से ऐसा करने के लिए युक्ति युक्त पूर्वक अपेक्षा की जाए; और

(चार) सामान्यतः ऐसे उपाय करना, जिनसे अग्नि लगने की संभावना कम हो या अग्नि के फैलाव को रोका जा सके।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों, अध्यादेश एवं नियमावली के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थ उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

कठिनाइयों दूर करने की
शक्ति

67-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने हेतु उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

अधिनियम का अन्य
विधियों पर अध्यारोही
प्रभाव होना

68-(1) जहाँ तक अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा से संबंधित उपबंधों का संबंध है वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित कोई बात की जानी या अनुमोदित की जानी अपेक्षित हो तब ऐसी कोई बात, केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य रूप से कृत या अनुमोदित की गयी नहीं समझी जाएगी कि तदनिमित्त ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा, स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव वाले किसी लिखित में अन्तर्विष्ट किसी तथ्य से असंबद्ध किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम और तद्विनिर्दिष्ट बनायी गयी नियमावली के उपबंध प्रभावी होंगे।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रवर्तन वाले किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में ऊपर यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित बात के अतिरिक्त और उसके सिवाय नहीं होंगे।

69 - जहां महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी ,जो अग्निशमन या किसी आपात कार्य संचालन का प्रभारी हो, किसी अन्य प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन उपस्कर तथा उपकरण या संपत्ति की अपेक्षा करे ,वहां वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में अग्नि बुझाने या किन्हीं अन्य आपात स्थितियों के प्रयोजनार्थ ऐसे उपस्कर या संपत्ति को अधियाचित कर सकता है और यथास्थिति प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति से उसका कब्जा गृहीत कर सकता है ।

अग्निशमन संपत्ति अधियाचन

70 - (1) असाधारण वीरता और जीवन तथा संपत्ति को बचाने के कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित कर चुके उत्कृष्ट खिलाड़ियों ,निशानेबाजों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों को रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अर्धधीन अगले उच्चतर रैंक के लिए बिना पारी पदोन्नति कर सकता है ;

अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारिवृंद की विशेष पदोन्नति

(2) ऐसी पदोन्नति या ऐसे रैंकों में स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी ;

(3) ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों को उस वर्ष तैयार की गई पदोन्नति सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में विधिक तथा संरचनात्मक रूप से सुसज्जित अग्निशमन तथा आपात सेवा की आवश्यकता है ,जो जीवन सुरक्षा ,बचाव कार्य और अन्य आपात स्थितियों यथा बाढ़ ,भूकम्प ,भवन विध्वंस ,आणविक तथा जैविक परिसंकरों हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित हो ।

पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के निमित्त सम्पूर्ण भारत में अग्निशमन सेवा अधिनियमों में एकरूपता लाये जाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा अंगीकृत किये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा आदर्श अग्निशमन सेवा विधेयक 1958 ,और संशोधित आदर्श अग्निशमन तथा आपात विधेयक 2019 ,परिचालित किये गये थे ।

भविष्य में बढ़ते औद्योगिक विकास ,नगरीकरण ,आपदाओं तथा सम्भावित अग्नि दुर्घटनाओं के कारण यू0पी0 अग्निशमन सेवा अधिनियम , 1944 (यू0पी 0अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) और उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005) आगामी तथा भावी अपेक्षाओं को पूरा करने योग्य नहीं थे । इसके साथ ही साथ 'अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र ' पूर्वोक्त अधिनियमों का अभिन्न अंग न होने के कारण भवनों तथा परिसरों में अग्नि सुरक्षा तंत्र अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना सम्भव नहीं था ।

पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा परिचालित आदर्श अग्निशमन तथा आपात विधेयक 2019 ,उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने का विनिश्चय किया गया ।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2022 ,को उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश , 2022 प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र ।

1- उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 की धारा-52 में निधि के गठन का प्रावधान है । उक्त विधेयक के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीस, कर और शास्तियों (जुर्माने से भिन्न) के आगमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

2- उक्त विधेयक लागू होने पर जनशक्ति एवं संसाधन बढ़ाये जाने की आवश्यकता होगी, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार अवश्य आएगा, जिसका अनुमान लगाया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022 ,में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अंतर्गस्त हैं ।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक 2022 ,में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्न प्रकार है:-

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1 (3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसे दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रही है ,जबसे अधिनियम प्रवृत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे ।
3 परन्तुक	इसके द्वारा राज्य सरकार को सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अग्निशमन दल या किसी अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा, चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, को यह घोषित करने की शक्ति दी जा रही है कि उक्त दल या सेवा किसी भी समय राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग होगा अथवा नहीं होगा ।
3 (2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम अथवा स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी अग्निशमन दल या अग्नि रोकथाम से सम्बन्धित सेवा को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांको से राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग घोषित किये जाने की शक्ति दी जा रही है ।
5 (3)	इसके द्वारा राज्य सरकार को सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य में विद्यमान अग्निशमन तथा आपात सेवा की पद्धति की समीक्षा करने और यदि वह उचित समझे तो उसे उपान्तरित करने की शक्ति दी जा रही है ।
8 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को राज्य के भीतर अग्निसुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उतने अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों का सृजन करने की शक्ति दी जा रही है ।

23, 24	इसके द्वारा राज्य सरकार को किसी क्षेत्र के भवनों /परिसरों /पण्डालों जहाँ आग का खतरा होना सम्भावित हो ,के स्वामी /अध्यासी को सावधानियां बरतने हेतु अधिसूचना प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।
41 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को प्रशमन हेतु अधिसूचना जारी कर शुल्क निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।
48 (2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को गजट में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर अवधारित अग्निशमन कर निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।
54	इसके द्वारा राज्य सरकार को उ0प्र 0अग्निशमन एवं आपात सेवा को प्राविधिक सेवा घोषित करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।
64 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।
65 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ,ऐसी शर्तों ,यदि कोई हो ,जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों ,के अधीन किसी अधिकारी को शक्ति प्रदान की जा रही है ।
67 (1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर अधिनियम के उपबन्धों की विसंगतियों को दूर करने की शक्ति प्रदान की जा रही है ।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2022) के उपबन्धों से उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक , 2022 में किये गये रूप-भेदों का ज्ञापन ।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन 2022) के उपबन्धों को उसी रूप में और कतिपय संशोधनों के साथ सम्मिलित किया गया है | विधेयक में किये जाने वाले रूप भेदों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में परिभाषा में खण्ड 2(ग) में शब्द "और इस अध्यादेश की धारा 24 की उपधारा (3) में परिभाषित हो" को विलोपित किया जा रहा है ।
2. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में परिभाषा में खण्ड 2 (ड) में शब्द "नियमावली में विहित" के पश्चात "अग्नि सुरक्षा तन्त्र सहित" जोड़ा जा रहा है तथा अंक "26" के स्थान पर "28" किया जा रहा है ।
3. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में परिभाषा में खण्ड 2 (ढ), (ण) में अंक "8, 51" के स्थान पर क्रमशः "9, 52" किया जा रहा है ।
4. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 6 (2) में शब्द "वास्तविक, ज्ञान, अनुभव" के स्थान पर शब्द "वास्तविक, अर्हता, ज्ञान, अनुभव" किया जा रहा है ।
5. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 9 (2) में शब्द तथा अंक "धारा 8 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "इस धारा की उपधारा (1)" किया जा रहा है ।

6. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 17 में शब्द "अग्नि" के पश्चात शब्द "और / या" बढ़ाया जा रहा है।
7. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 21, 24, 25 में अंक "15, 21, 38, 21, 22" के स्थान पर अंक क्रमशः "17, 23, 39, 23, 24" किया जा रहा है।
8. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 26 में शब्द "संहिताओ" के स्थान पर "संहिता" तथा शब्द "राष्ट्रीय भवन संहिताओ" के स्थान पर "उप विधियों" किया जा रहा है।
9. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 27 में अंक "24" के स्थान पर अंक "26" किया जा रहा है।
10. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 33 में अंक "26" के स्थान पर अंक "28" तथा शब्द "स्वामित्र प्राप्त/ अध्यासन प्राप्त क्षेत्र" के स्थान पर "स्वामित्र प्राप्त/ अध्यासन प्राप्त कुल निर्मित क्षेत्र" किया जा रहा है।
11. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 34, 36 में अंक "15, 21" के स्थान पर अंक "17, 23" किया जा रहा है।
12. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 40 में शब्द "महानिदेशक" के स्थान पर शब्द "निदेशक" किया जा रहा है।
13. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 41 में अंक "31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38" के स्थान पर अंक क्रमशः "33, 34, 35, 36, 37, 38, 39" किया जा रहा है।
14. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 44 में शब्द "मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय" के स्थान पर "न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय" किया जा रहा है।
15. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 52 में शब्द "सामुदायिक तैयारी" के पश्चात शब्द "अवसंरचना" जोड़ा जा रहा है।
16. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 58 में अंक "24" के स्थान पर अंक "29" किया जा रहा है।
17. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 52 में शब्द "पुलिस बल" के पश्चात शब्द "एवं अन्य संबंधित विभाग" जोड़े जा रहे हैं।
18. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 66 में शब्द "संयुक्त प्रान्त" के स्थान पर शब्द "यू0पी0" जोड़ा जा रहा है।
19. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2022 में खण्ड 68 के पार्श्व शीर्षक में शब्द "अध्यादेश का अभिभावी प्रभाव होना और अन्य विधियों पर प्रभाव होना" के स्थान पर शब्द "अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना" जोड़ा जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 604/XC-S-1-22-28S-2022

Dated Lucknow, December 08, 2022

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "Uttar Pradesh Agnishaman Tatha Aapaat Seva Vidheyak, 2022" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 06, 2022.

THE UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES BILL, 2022

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

A

BILL

to provide for the maintenance of fire and emergency services for the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

- | | |
|---|---|
| <p>1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022.</p> <p>(2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.</p> <p>(3) It shall come into force in any area on such date as the State Government may, by notification in the Official <i>Gazette</i> appoint, and different dates may be appointed for different areas and for different provisions of this Act.</p> | <p>Short title,
extent and
commencement</p> |
| <p>2. In this Act, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) "Appellate Authority" means an Officer appointed by the State Government, who is at least two ranks higher than the Fire Officer as defined in Section 45 of this Act;</p> <p>(b) "Building" shall have the same meaning assigned to it in the relevant municipal law or any law for the time being in force in the area in which this Act is in force and includes places or premises comprising land or building, or part of a land or building, whether authorized or otherwise, outhouses, if any, pertaining to such building or part thereof and petrol, diesel or gas lines, installations or pumps;</p> | <p>Definitions</p> |

(c) “Building bye-Laws” means the building bye-laws, rules and regulations made under any relevant municipal law and includes the development control rules or regulations, by whatever name they are called, or any other building rules or regulations made under any other law for the time being in force and are in the area in which this Act is in force;

(d) “Bureau of Indian Standard (BIS)” means National Standard body of India established under Bureau of Indian Standards Act, 2016 (Act no. 11 of 2016);

(e) “Bye law” means fire safety regulations or norms or guidelines made under National Building Code of India, Building Bye-laws enacted by Entity Authority, Oil Industry Safety Directorate guidelines, Petroleum Act and Rules, Explosive Act and Rules of India relating to fire prevention, or any relevant guidelines by the State Government or local Authority as amended from time to time;

(f) “Director” means the Director of the Fire and Emergency Services appointed by the State Government under section 6 of this Act;

(g) “Director General” means the Director General of the Fire and Emergency Services appointed by the State Government;

(h) “Disaster” means disaster as defined in Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005) as amended from time to time;

(i) “Emergency” means any serious situation or occurrence, including disasters, that happens unexpectedly and demands immediate action of Fire and Emergency Service of the State Government or Local Authority;

(j) “Employee” means a person appointed to the Fire and Emergency Service under this Act;

(k) “Entity Authority” shall include a Local Authority, Development Authority, Municipality, Municipal Corporation, Awas Vikas Parishad or Building Plan Sanctioning Authority;

(l) “Erector” means a person or association of persons, whether corporate or otherwise, who erects or makes a pandal or any structure for occupation of people on a regular or temporary basis;

(m) “Fire Prevention and Life Safety Measures” means such measures inclusive of fire protection system as are necessary in accordance with the National Building Code of India for the containment, control, and extinguishing of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire and as may be prescribed in the Rules made in this behalf;

(n) “Fire Safety Officer” means the person appointed under section 28 of this Act by the owner or occupier of certain premises and buildings as specified in this behalf to ensure fire prevention and fire safety measures installed in such premises and buildings;

(o) “Fire Officer” means an officer appointed by the State for fire stations and other field formations as per section 9 of this Act;

(p) "Fire Station" means a building erected to house the firefighting equipment, appliances and staff declared generally or specially by the State Government to be a Fire Station and other field formations for the purpose of this Act;

(q) "Fund" means fund constituted under section 52 of this Act;

(r) "Local Authority" shall mean a Municipal Board or Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Notified Area Committee, Town Area Committee, Zila Parishad, Cantonment Board, Kshetra Samiti, Gaon Sabha or any other authority constituted for the purpose of Local Self-Government or village administration or legally entitled to or entrusted by the State Government with the control or management of municipal or local fund;

(s) "Local Fire and Emergency Service" means Local Fire and Emergency Service as may be notified by the State Government;

(t) "National Building Code" means the book or books containing Fire Prevention and Life Safety Measures to be implemented in the buildings, places, premises, workshops, warehouses and industries, published from time to time by the Bureau of Indian Standards;

(u) "Occupancy" means the principal occupancy for which a building or a part of the building is used or intended to be used including subsidiary occupancies which are contingent upon it;

(v) "Occupier" means,—

(i) any person who, for the time being, is paying or is liable to pay, to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;

(ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;

(iii) a rent-free tenant of any land or building;

(iv) a licensee in occupation of any land or building; and

(v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;

(w) "Owner" includes a person who, for the time being, is entitled to receive the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person, or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant;

(x) "Pandal" means a temporary structure with a roof or walls made of straw, hay, ulu grass, golpatta, hogla, darma, mat, canvas, cloth or other like material which is not adopted for permanent or continuous occupancy;

(y) "Second Appellate Authority" means an Officer appointed by the State Government, who is at least one rank higher than the Appellate Authority as defined in section 45 of this Act;

(z) "Standing Fire Advisory Council (SFAC)" means the advisory body constituted by the Union Ministry of Home Affairs to examine the technical problems relating to Fire Service and to make recommendation to the Government of India in the matter including the standardization of fire-fighting equipment through the Indian Standard Institutions;

(aa) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

(bb) "Qualified agency" means a person or an association of persons having technical specialization in the field of Fire from a recognized University and having sufficient domain knowledge and accomplishments in the field of Fire Service.

CHAPTER II

ORGANIZATION, SUPERINTENDENCE, CONTROL, AND MAINTENANCE OF
THE FIRE AND EMERGENCY SERVICE

Establishment of
one Fire and
Emergency
Service for whole
of State of Uttar
Pradesh

3. (1) There shall be one Fire and Emergency Service for the whole of State of Uttar Pradesh and all officers and subordinate ranks of the Fire and Emergency Service shall be liable for posting to any branch of the Fire and Emergency Service:

Provided that the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare any Fire Brigade or any other Local Fire and Emergency Service of any local authority of the state, by whatever name called, that the same shall form or shall not form the part of State Fire and Emergency Service at any time:

Provided further that this provision shall not apply to the private Fire and Emergency Services maintained for providing fire protection coverage to a specific building or industry by the owner or occupier thereof.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force relating to the Local Authority, the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, declare the services relating to any fire brigade or fire prevention a part of the State Fire and Emergency Service with effect from such dates as may be specified in the notification.

(3) In order to assist any disaster, other than resulting due to fire, all Fire Services shall be considered as Emergency Services:

Provided that in case where the emergency service is not related only to fire, the decisions and directions of the authority in charge of the Emergency Service shall prevail.

Superintendence
of Fire and
Emergency
Service to vest in
State Government

4. The superintendence of, and control over, the Fire and Emergency Service throughout the State shall vest in the State Government and the Fire and Emergency Service shall be administered by the State Government in accordance with the provisions of this Act and / or any rule made thereunder, through such Fire Officers as the State Government may, from time to time, appoint in this behalf.

Constitution and
Classification of
Fire and
Emergency
Service

5. (1) Subject to the provisions of this Act, the State Fire and Emergency Services shall consist of such number of staff in various ranks and have such organizations and have such powers, functions and duties as the State Government may, by general or special order, determine.

(2) The State Government may prescribe by rules,—

(i) the different posts of the State Fire and Emergency Service;

(ii) the mode of recruitment of staff, grade of post, the qualification, pay, allowances and other conditions of service of the officers and other staff engaged therein and matters connected therewith.

(3) The State Government may, by notification in the Official *Gazette*, review the pattern of the existing Fire and Emergency Service in the State and if deem fit may modify the same:

Provided that for local Fire and Emergency Services, the rules framed under this sub-section may not include mode of recruitment of staff, pay, allowances and matters connected therewith.

(4) Save as otherwise provided by or under this Act, every person holding office either as a Fire Officer or staff or an employee (by whatever designation called) of an existing Fire Brigade or Fire and Emergency Services of any Authority on the date immediately before the commencement of this Act, shall continue to hold office on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before such date and shall exercise such powers and perform such duties as before and in addition to those as are conferred on them by or under this Act.

6. (1) The State Government shall appoint an officer of the rank of Director General of Police/Additional Director General of Police as Director General Fire and Emergency Service hereinafter referred as Director General Fire and Emergency Services who shall exercise such powers and perform such duties and other functions as are specified under this Act and whose jurisdiction shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

Appointment of Director General and Director of Fire and Emergency Service

(2) The State Government shall appoint a Fire Officer of domain Qualification knowledge experience and credible accomplishments in the field of fire service to be the Director, Fire and Emergency Services who shall exercise such powers and perform such duties and other functions as are specified by or under this Act.

(3) The State Government shall appoint such other officers and staff, as may be necessary from time to time, to assist the Director General, Fire and Emergency Services and Director, Fire and Emergency Services while exercising the powers or discharging the duties or functions conferred under this Act or rules made thereunder.

(4) Subject to the control, directions and superintendence of the State Government, the Director General and the Director shall exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed upon him by this Act or the rules made thereunder.

7. (1) The Director General, Fire and Emergency Services shall subject to the superintendence and control of the State Government, direct and regulate all matters of fire safety and prevention, firefighting equipment, machinery and appliances, training, observation of persons, events of mutual relations, distribution of duties, study of laws, orders and modes of proceedings and all matters of executive detail or the fulfillment of duties and maintenance of discipline of fire officers and employees of the Fire and Emergency Service under him, as per the relevant State rules.

Power, Duties and Functions of the Director General Fire and emergency services

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (4) of section 6, the Director General, Fire and Emergency Services shall,-

(i) function as the Head of the Department in the office of the Director General, Fire and Emergency Services;

(ii) keep liaison with the State Government for the development of Fire and Emergency Service;

(iii) frame the policies in relation to the development of Fire and Emergency Service in the State and, on approval by the State Government, take steps to implement the same;

(iv) prepare and submit plans and proposals to the State Government with regard to the periodical review of fire equipment, fire property and fire manpower for effective implementation of Fire and Emergency Service by the authorities;

(v) take or cause to be taken such effective steps and measures in cases of major fires, house collapse and other emergency services;

(vi) investigate or cause to be investigated the cause of fire and advise the authorities for implementing fire precautionary measures;

(vii) implement the effective Human Resource Development policies of the State Government in accordance with the prescribed jobs at each level of fire service personnel and for that purpose, he may establish advance training centers;

(viii) represent the State Government on National and International forums with a view to updating the standard of Fire and Emergency Service in the State;

(ix) exercise such other powers and perform such other duties and functions as may be conferred, imposed or allotted to him by or under the provisions of this Act.

Setting up of
Fire Stations

8. (1) For the purpose of providing adequate number of officers and staff for meeting the needs of fire service, having regard to the population, potential fire hazards in certain industries and large commercial and mercantile establishments and buildings and fire stations required to be provided for and maintained, the State Government may, for the purpose of securing fire prevention and life safety measures within the State, by notification in the Official *Gazette*, constitute as many Fire Stations and other field formations as it deems fit.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the Fire Stations and other field formations to which it relates and shall define the limits and extent of Fire Stations and other field formations as may be necessary for administrative and operational efficiency.

Appointment,
powers, duties
and functions of
Fire Officers

9. Appointment of Fire Officers:

(1) For the purposes of this Act, the State Government may appoint,-

(a) A Fire Officer, for each Fire Station not below the rank of Fire Station Second Officer as authorized by the Director, Fire and Emergency Services who shall be officer-in-charge of a Fire Station and shall hold charge of a Fire Station as per the size of the Fire Service as specified by the Director, Fire and Emergency Services.

(b) He shall have such staff under him to the Fire Station as may be determined by the State Government.

(c) He shall be responsible for maintenance of communication system, water resources including hydrants within his station areas, and shall be in charge of operations of Fire and Emergency Services.

(d) Similar arrangements shall be provided for other field formations, if any.

Powers, duties and functions of Fire Officers :

(2) The powers, duties and functions of the Fire Officers shall be as follows:-

(a) Subject to the control, direction and superintendence of the Director General, the Fire Officer appointed under sub-section (1) of this section of the Act, shall exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed upon him by this Act or rules or orders made thereunder.

(b) Without prejudice to the provisions of clause (a) in case of fire prevention and disaster, the Fire Officer or officers appointed under sub-section (1) of this section, for their jurisdiction, shall, in case of any fire or emergency, Act as Commanding Officer for that event and other Fire and Emergency Service engaged shall work under him.

Appointment,
powers, duties
and functions of
Other Officers

10. (1) For the purpose of this Act, the State Government may appoint other Officers and staff for the administrative purposes and other field formation as may be necessary from time to time.

(2) The qualifications for appointment and other conditions of service of the Officers appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed in the rules.

(3) For the purpose of this Act, the State Government shall appoint such officers as may be deemed necessary to supervise Fire Stations while exercising such powers or discharging the duties and functions under this Act or rules made thereunder.

Issue of
Certificate to the
employees of
Fire and
Emergency
Service

11. (1) Every person shall on appointment to the Fire and Emergency Service, receive a certificate in the prescribed form under the signatures of the Director General or an officer authorized in this behalf by the State Government and thereupon such person shall have the powers, functions and privileges of an employee of the Fire and Emergency Service under this Act.

(2) The certificate referred to in sub-section (1) shall cease to have effect when the person named therein ceases for any reason to be an employee of the Fire and Emergency Service and on his ceasing to be such employee, he shall forthwith surrender the certificate to any officer empowered to receive the same.

(3) A certificate of appointment shall become *null and void* when the person named therein ceases to belong to the Fire and Emergency Service or shall remain inoperative during the period such person is suspended from the Fire and Emergency Service.

(4) The employees of the Fire and Emergency Service shall be governed by such rules as are applicable to State Government servants in relation to the terms and conditions of their service and all other allied matters.

12. Whenever, it appears to the State Government that it is necessary to augment the Fire and Emergency Service, it may raise an auxiliary service by enrolment of volunteers for such area and on such terms and conditions as it may deem fit as per Rules. Auxiliary Fire and Emergency Service
13. The powers, functions and privileges vested in a Fire Officer shall remain suspended while such Fire Officer is placed under suspension: Effect of suspension of Fire Officer
 Provided that notwithstanding such suspension, such person shall continue to be subject to the control of same authorities to which he would have been had he not been placed under suspension.

CHAPTER III

FIRE AND EMERGENCY RESPONSE

14. The Fire Officer appointed by the State Government shall respond to all fire and emergency related calls as per Standard Operating Procedures prescribed by the rules. Calls related to any other emergencies shall also be entertained by the Fire and Emergency Services by order and as per rules. Response to Calls
15. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer shall ensure deployment of Fire and Emergency Service resources, equipments and fire personnel at stand-by duties during any fire response or any other emergency as specified in the rules. Personnel and scale of equipment
16. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer shall provide details of planning, organizing and deployment of the staff and ensure regular monitoring of the site as per rules. Operation Management
17. On the occasion of fire and/or rescue in any area in which this Act is in force, any member of the Fire and Emergency Services, who is in-charge of firefighting operations on the spot, may,- Powers of Employees of the Fire and Emergency Service on occasion of fire and/or rescue
- (a) remove, or order any other member of the Fire and Emergency Service to remove any person who by his presence interferes with or impedes the operation for extinguishing the fire or for saving life or property;
- (b) close any street or passage in or near which a fire is being fought and / or rescue work is in progress;
- (c) for the purpose of extinguishing fire and carrying out rescue operation, break into or through or pull down, any premises for the passage of hose or appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible for the purpose of extinguishing fire:
 Provided that the owner or occupier, as the case may be, of any such premises shall be paid reasonable compensation to the extent of the damage so caused in such manner as may be prescribed in the rules;
- (d) require the Authority in charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilize the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire and carrying out rescue operations ;
- (e) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the firefighting operations as if he were an officer-in-charge of a police station and as if such an assembly were an unlawful assembly and shall be entitled to the same immunities and protection as such an officer, in respect of the exercise of such powers;
- (f) arrest a person who wilfully obstructs and hinders a Fire and Emergency Service personnel in firefighting and rescue operations and shall hand him over to a police officer or at the nearest police station without avoidable delay along with a brief note giving the time, date and reason of arrest;
- (g) enter into agreement with any person who employs and maintains personnel or equipment or both for fire-fighting purposes, to secure, on such terms as may be prescribed, for the purpose of dealing with fires occurring in any area;
- (h) take such measures as may appear to him to be necessary for extinguishing the fire or for the protection of life or property, or both.

CHAPTER IV
WATER SUPPLY

Power to arrange for water supply during emergency	18. It shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer of the fire-fighting operations to draw water from any source in the area which he considers necessary during fire-fighting operations and on such occasions as may be required and the Authority or owner or occupier having control over such water source shall supply water for that purpose at such rates as may be prescribed.
Duty to arrange water supply	19. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer shall take all reasonable measures for securing that an adequate supply of water will be available for the use in the event of fire as per the Rules.
Power to enter into Agreement for Water Supply	20. The Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer may enter into an agreement with an agency for meeting demand of water supply and emergent need of water as per the procedures and terms and conditions for the payment to the third party, prescribed under the rules.
No compensation for interruption of water supply	21. No Authority in charge of water supply in any area shall be liable to any claim for compensation for damage by reason of any interruption of supply of water caused in compliance with clause (d) of section 17.
Compensation of water	22. No charge shall be made by any Local Authority for water consumed in fire fighting operations by the Fire and Emergency Service.

CHAPTER V

**GENERAL MEASURES FOR FIRE AND EMERGENCY PREVENTION
AND LIFE SAFETY MEASURES**

Preventive Measures	<p>23. (1) The State Government may, by notification, require owner or occupier of premises in any area or of any class of premises used, which in its opinion, are likely to cause risk of fire, to take such precautions as may be specified in such notification.</p> <p>(2) Where such notification has been issued, it shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services or Fire Officer to direct the removal of objects or goods likely to cause the risk of fire, to a place of safety and on failure by the owner or occupier to do so, the Director or Fire Officer may, after giving the owner or occupier a reasonable opportunity of making the representation, seize, detain or remove such objects or goods.</p> <p>(3) The Director, Fire and Emergency Services shall ensure that Fire and Emergency Management Plans of the Fire Stations and other field formations should be prepared in conformity with the respective District Disaster Management Plans.</p>
Fire Prevention and Life Safety measures in the pandals to be self-regulatory	<p>24. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the erectors of pandals shall be deemed to be self-regulators for taking fire prevention and life safety measures prescribed under section 23.</p> <p>(2) The erector of a pandal shall display at a prominent place in the pandal, a declaration in the prescribed form and under his/her own signature to the effect that he / she has taken all the prescribed fire prevention and fire safety measures therein as notified by the State Government.</p> <p>(3) It shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services to enter and inspect the pandal with a view to verify the correctness of the declaration so made by the erector under sub-section (2) and to point out the shortcomings, if any, with directions to remove them within a specified time. If the directions of the inspecting officer are not complied with within the time so given, the inspecting officer shall seal the pandal.</p> <p>(4) Any erector of a pandal who falsely declares that he has complied with the prescribed fire prevention and fire safety measures in the pandal shall be deemed to have committed an offence punishable under section 39 of this Act.</p>

25. (1) Where a notification has been issued under section 23 and section 24, it shall be lawful for the Director, Fire and Emergency Services to direct the removal of encroachments or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to firefighting, to a place of safety, and on failure of the owner, occupier or erector, as the case may be, to do so, the Director or Fire Officer may, after giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation, report the matter to the Sub-Divisional Magistrate, in whose territorial jurisdiction the premises or building or pandal is situated, requesting to adjudicate the matter:

Removal of encroachments or objects or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to fire fighting

Provided that where the Director, Fire and Emergency Services considers such encroachments or objects or goods to be an imminent cause of risk of fire or obstruction to firefighting, he may direct the owner or the occupier or erector of such premises or building to remove the encroachment or objects or goods forthwith and report the matter to the Sub-Divisional Magistrate accordingly.

(2) On receipt of a report under sub-section (1), the Sub-Divisional Magistrate shall give, by means of a notice served in such manner as he may think fit, a reasonable opportunity of showing cause against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk of fire or obstruction to firefighting.

(3) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation under sub-section (2), the Sub-Divisional Magistrate may make an order to seize, detain or remove such encroachments or objects or goods as per prescribed rules.

(4) The person charged with the execution of the order as made in sub-section (3) shall forthwith make an inventory of the objects and goods which he seizes under such order, and shall, at the same time, give a written notice as may be prescribed in this behalf, to the person in possession thereof at the time of seizure, that the said objects or goods will be sold as therein mentioned if the same are not claimed within the period stipulated in the said notice.

(5) On the failure of the person in whose possessions the objects or goods were at the time of seizure to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-section (4), the Sub-Divisional Magistrate shall sell them accordingly by public auction.

26. (1) Without prejudice to the provisions of National Building Code of India, Building Bye-laws of respective entity authorities, any other law or Bye-Law, the owner or the occupier, who are either individually or jointly responsible, of a building as classified by regulations or part thereof, shall provide fire prevention and life safety measures therein:

Owner or Occupiers liability to provide Fire Prevention and Life Safety Measures

Provided that the owner or the occupier, as the case may be, shall,-

(i) provide minimum fire-fighting and life safety installations as provided in the Bye-Laws;

(ii) maintain the fire prevention and life safety measures in operational condition at all times, in the manner and specifications specified in Bye-Laws.

(2) Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, no authority empowered to issue the occupancy certificate, shall issue the same, unless it is satisfied that the owner or the occupier, either individually or jointly, has complied with the provision as given in sub-section (1) of this section.

(3) Without prejudice to the existing Building Bye-laws applicable and enforcement of bye-laws by the State, following buildings shall obtain 'Fire Safety Certificate' from Fire and Emergency Services;

(i) Multi-storied buildings having more than 15 meters height;

(ii) Special buildings like educational, institutional, assembly, business, mercantile, industrial, storage and hazardous buildings as defined in National Building Code as amended from time to time;

(iii) Mixed occupancies with any of the aforesaid occupancies having more than 500 square meter covered area.

(4) Owners of Buildings, under sub-section (3), shall ensure that such multi-storied or special buildings be equipped with fire prevention, fire and life safety and fire protection system to prevent or extinguish fire as per the prescribed rules.

(5) The owner or occupier, as the case may be, shall furnish to the Fire Officer, a certificate in the prescribed form issued by a qualified agency regarding the compliance of the fire prevention, fire and life safety measures and fire protection measures in his building or part thereof, as required by or under the provisions of this Act, and shall also furnish to the Fire Officer a certificate in the prescribed form twice a year in the months of January and July regarding the maintenance of fire protection system in good repair and efficient condition as specified in sub-section (1) of this section.

(6) No person other than the qualified agencies, as specified in the National Building Code of India or rules made under this Act, shall carry out the work of providing fire prevention and life safety measures or performing such other related activities required to be carried out in any place or building or part thereof.

Issue of Fire
Safety
Certificate

27. (1) The Fire Officer shall scrutinize the compliances with regard to the requirement of section 26 made by owners or occupiers or applicant, as the case may be, either independently or jointly, after making necessary inquiry, if any, issue fire safety certificate within a month of the application subject to the condition that all necessary documents, designs, maps, completion certificates *etc.* shall be submitted by the owner or occupier or applicant.

(2) If the owner or occupier, as the case may be, fails to comply with the directions issued by the Fire Officer, the fire safety certificate, issued under section 26 of this Act, shall be cancelled after giving owner or occupier an opportunity of hearing to show-cause.

(3) The owner or occupier of the building or premises, whose fire safety certificate has been cancelled due to default on his part, shall not be entitled to occupy the building or premises on the ground of non-compliance of fire prevention and life safety measures under section 26 of this Act.

(4) No person shall tamper with, alter, remove or cause any injury or damage to any fire prevention and life safety equipment installed in any such building or part thereof or instigate any other person to do so.

Appointment
and Functions of
Fire Safety
Officer

28. (1) To ensure effective fire prevention and life safety measures of the factory or buildings or premises as may be specified by an order by the State Government in this behalf, every owner and occupier or occupiers individually or jointly, as the case may be,-

(i) shall appoint a fire safety officer, having such qualifications as may be prescribed;

(ii) send the compliance report to the Fire Officer.

(2) The Fire Safety Officer so appointed under sub-section (1) shall be issued the enrolment certificate by the Fire Officer under his signature and seal of the office in the prescribed form.

(3) In case of a vacancy of the Fire Safety Officer appointed under sub-section (1), either on resignation or otherwise, the owner and occupier or occupiers individually or jointly, as the case may be, shall be required to immediately appoint the fire Safety Officer.

(4) In case of the non-appointment of the Fire Safety Officer, as envisaged under sub-section (1), the Fire Officer may take such steps as he deems necessary, which includes report to the Labour Commissioner for the closure of the factory and in other cases to the relevant authority for necessary action under relevant law.

(5) The Fire Safety Officers shall undergo training at the Fire and Emergency Service Training Institute as may be specified by the State Government in this behalf:

Provided that a person who has already undergone such training at the National Fire Service College, Nagpur or at any other equivalent institution recognized by the State Government, shall not be required to undergo such a training.

29. (1) The Fire Officer may, after giving three hours' notice to the occupier, or if there is no occupier, to the owner of any place or building or part thereof, enter and inspect such place or building or part thereof at any time between sunrise and sunset where such inspection appears necessary for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and life safety measures:

Power of
Inspection

Provided that the Fire Officer may enter into and inspect any such place or building or part thereof at any time if an industry is working or an entertainment is going on at such place, building or part thereof, or if it appears to him to be expedient and necessary to do so in order to ensure safety to life and property.

(2) The Fire Officer shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, of such place or building or part thereof for carrying out the inspection under sub-section (1).

(3) The owner or occupier or any other person shall not obstruct or cause any obstruction to the entry of a person empowered or authorized under this section into or upon any land or building or shall not molest such person after such entry for inspection.

(4) When any such place or building or part thereof used as a human dwelling is entered under sub-section (3), due regard shall be paid to the social and religious sentiments of the occupiers, and before any flat, apartment or a part of such building in the actual occupancy of any woman, who, according to the custom does not appear in public, is entered under sub-section (3), notice shall be given to her that she is at liberty to withdraw, and every reasonable facility shall be afforded to her for withdrawing.

(5) Where the inspection is carried out by the Fire Officer under the preceding provisions of this section, he shall give a report of any such inspection to his reporting officer and the Entity Authority concerned.

(6) The Fire Officer shall, after completion of the inspection of the place or building or part thereof under this Section, record his views on the deviations from or the contraventions of, the requirements with regard to the fire prevention and life safety measures or the inadequacy or non-compliance of such measures provided or to be provided therein with reference to the height of the building or the nature of activities carried on in such place or building or part thereof and issue a notice to the owner or occupier of such building or part thereof directing him to undertake such measures within such time as may be specified in the notice.

30. Any person who possesses any information regarding an outbreak of fire shall communicate the same without delay to the nearest fire station.

Information on
outbreak of
fire

CHAPTER VI

OFFENCES AND PENALTIES

31. Whoever contravenes any provisions of Chapter IV shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to three thousand rupee for every day after the first during which such offence continues.

Penalties for
violation of
provisions of
Chapter IV
(Water
Supply)

32. Notwithstanding any action which may be taken under the provisions of this Act, any member of the Fire and Emergency Service who,-

Penalty for
violation of
duty

(i) is found to be guilty of any violation of duty or wilful breach of any provision of this Act or any rule or order made thereunder; or

(ii) is found to be guilty of cowardice; or

(iii) withdraws or abstains from the duties of his office without permission or without having given previous notice for fifteen days or more; or

	(iv) being absent on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on expiration of such leave; or
	(v) accepts any other employment or office or engages himself in business in contravention of the provision of the Uttar Pradesh Government Servant Conduct Rules, 1956 shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to an amount not exceeding three months pay of such member, or with both.
Penalty in case of non-appointment of Fire Safety Officers	<p>33. (1) If any owner or occupier or an association of such owners and occupiers of a building or premises fails to appoint under section 28, Fire Safety Officers within thirty days, of the receipt of a notice given in this behalf by the Director, Fire and Emergency Services or the Fire Officer, as the case may be, each one of them shall be deemed to be in default jointly and severally.</p> <p>(2) When the person liable for appointment of such Fire Safety Officers is deemed to be in default, such sum not less than ten rupees per square meter and not exceeding fifty rupees per square meters of total built-up area owned/occupied by him including in the common areas in the premises as determined by the Director, Fire and Emergency Services may be recovered from him by way of penalty for each month of default or part thereof.</p> <p>(3) The amount due as penalty under sub-section (2) shall be recovered as arrears of land revenue.</p>
Liability of property owner to pay compensation	<p>34. (1) Any person whose property catches fire on account of an action of his own or of his agent done deliberately or negligently shall be liable to pay compensation to any other person suffering damage to his property on account of any action taken under section 17 of this Act by an officer mentioned therein or any person acting under the authority of such officer.</p> <p>(2) All claims under sub-section (1) shall be referred to the Appellate Authority, within thirty days from the date when the damage was caused.</p> <p>(3) The Appellate Authority, shall, after giving the party an opportunity of being heard, determine the amount of compensation due and pass an order stating such amount and the person liable for the same, and the order so passed shall have the force of a decree of a Civil Court within thirty days as mentioned in section.</p>
Failure to give information	35. Any person, who without adequate justification, fails to communicate information in his possession regarding an outbreak of fire shall be deemed to have committed an offence punishable under the first part of section 176 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).
Failure to take precautions	36. Whoever fails without reasonable cause to comply with any of the requirements specified in a notification issued under sub-section (1) of section 23 or of a direction issued under the section shall be punishable with fine which may extend to Ten thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to One thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.
Penalty for wilfully obstructing the fire-fighting, rescue operations	37. Any person who wilfully obstructs or interferes with any member of the Fire and Emergency Services, who is engaged in fire-fighting operations, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to Ten thousand rupees, or with both.
False report	38. Any person who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to Ten thousand rupees, or with both.

<p>39. Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule or notification made thereunder shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to Ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to One thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.</p>	<p>General provisions for punishment for offence</p>
<p>40. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.</p> <p>(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part, of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Explanation:—</i> For the purposes of this section,-</p> <p style="padding-left: 80px;">(i) ‘Company’ means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and</p> <p style="padding-left: 80px;">(ii) ‘Director’, in relation to a firm, means a Partner in the firm.</p>	<p>Offences by companies</p>
<p>41. (1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under sections 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 or any rule made under this Act, may either before or after the institution of prosecution, be compounded by such officers of the Fire and Emergency Service and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the State Government or of any of the officers authorized under this Act and until the same has been complied with so far as the compliance is possible.</p> <p>(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.</p>	<p>Compounding of offences</p>
<p>42. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.</p>	<p>Protection of action taken in good faith</p>
<p>43. No Court shall proceed to the trial of an offence under this Act, except on the complaint of, or upon information received from, the Director, Fire and Emergency Services or the officer authorized by him in this behalf.</p>	<p>Cognizance of prosecution</p>
<p>44. Court of Judicial Magistrate shall try an offence punishable under this Act.</p>	<p>Jurisdiction</p>

CHAPTER VII**APPEALS**

Appeals

45. (1) Any person aggrieved by any notice or order of the Sub-Divisional Magistrate or Fire Officer or the Director, Fire and Emergency Services or Director General, Fire and Emergency Services issued or made under this Act may prefer an appeal against such notice or order to the Appellate Authority within thirty days from the date of the notice or order appealed against:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal to the Appellate Authority shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be specified in the rules framed under this Act.

(3) An order of the Appellate Authority on an appeal may be referred to the Second Appellate Authority and the decision of the Second Appellate Authority will be deemed final.

CHAPTER VIII**TRAINING**Establishment of
Fire and
Emergency
Training
Institute

46. (1) The State Government may establish and maintain one or more training centers in the State for providing courses of instruction in the prevention and extinguishment of fire and may close down or re-establish any such center.

(2) The State Government may extend the training facilities at the academy to be established under sub-section (1) to the Fire and Emergency Service under the control of local bodies and industrial undertakings as well as to the State Fire and Emergency Service of other States on payment of charges as may be prescribed.

(3) The State Government may prescribe such fee and such procedure as it may deem fit for providing a course of instruction in the prevention and extinguishment of fire.

(4) Subject to the observance of general rules applicable to other employees of the Government in relation to training, the employees of the Fire and Emergency Service may be given training in the field of scientific and modern techniques of fire protection and fire safety measures, and allied matters in any institute, within or out of India at the cost and expense of the State Government for the administration of the provisions of this Act.

Community
Preparedness

47. (1) The Fire Officer as authorized by the Director General, Fire and Emergency Services shall conduct community awareness and training programmes on preventive measures on fire and other emergencies.

(2) The Fire and Emergency Services shall render assistance and consultation to the communities in matters related to fire prevention as per rules.

CHAPTER IX**LEVY OF FIRE TAX, FEE AND OTHER CHARGES**

Levy of fire tax

48. (1) There may be levied a fire tax on Lands and Buildings which are situated in any area in which this Act is in force and on which property tax by whatever name called is levied by any local authority in that area.

(2) The fire tax shall be levied in the form of a surcharge on the property tax at such rate in terms of percentage of such property tax as the State Government may, by notification in the Official Gazette, determine from time to time.

(3) No fee shall be levied on any building vested in or under the control or possession of the Government or public Authority owned by the Government.

49. (1) The authorities empowered to assess, collect and enforce payment of property tax under the law authorizing the local authority of the area to levy such tax shall, on behalf of the State Government and subject to any rules made under this Act, assess, collect and enforce payment of the fire tax in the same manner as the property tax is assessed, paid and collected; and for this purpose, they may exercise all or any of the powers they have under the law aforesaid and the provisions of such law including provisions relating to returns, appeals, reviews, references and penalties shall apply accordingly.
- (2) Such portion of the total proceeds of the fire tax as the State Government may determine shall be deducted to meet the cost of collection of the fire tax.
- (3) The proceeds of the fire tax collected under this Act reduced by the cost of collection shall be paid to the State Government in such manner and at such intervals as may be prescribed.
50. (1) Where employees of the Fire and Emergency Service are sent beyond the limits of any area in which this Act is in force, in order to extinguish a fire in the neighborhood of such limits on the request of any State Government or local body or Fire and Emergency Service authority shall be liable to pay such fee as may be prescribed by the State Government from time to time in this behalf.
- (2) The fee referred to in sub-section (1) shall be payable within one month of the service of a notice of demand by the Director General, Fire and Emergency Services to the concerned State Government or local body or Fire and Emergency Service authority, as the case may be, and if it is not paid within that period, it shall be recoverable as an arrear of land revenue.
51. Any amount payable under this Act shall be recovered as arrears of land revenue.

Mode of assessment, collection, *etc.* of fire tax

Fee on deployment of Fire and Emergency Service beyond the limits of the State

Recovery of Dues

CHAPTER X FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY FUND

52. (1) There shall be constituted a fund to be known as "Fire Prevention and Life Safety Fund".
- (2) The proceeds of fire fees, tax and penalties (other than fines) recovered under this Act, shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and after deduction of the expenses of collection and recovery therefrom, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in, and transferred to, Fund constituted under sub-section (1).
- (3) Any amount transferred to the fund under sub-section (2) shall be charged on the Consolidated Fund of the State.
- (4) The amount of the fund shall be expended in such manner and under such conditions as may be prescribed, for the purposes of this Act.
- (5) The fund shall be reflected into the budget estimate of the respective authority and the accounts in respect thereof shall be maintained and audited in accordance with the procedure prescribed for this purpose of maintenance of accounts on the relevant law or the rules and orders made thereunder as are applicable to the respective authority.
- (6) The fund shall be utilized for community preparedness, infrastructure, training and procurement of fire-fighting equipment as prescribed in the rules.

Constitution of Fund

CHAPTER XI
MISCELLANEOUS

Reciprocal fire-fighting arrangements with other Fire and Emergency Service	53. The Director General, Fire and Emergency Services or any Fire Officer authorized by the State Government may, with the previous sanction of the State Government, enter into an agreement with any Fire and Emergency Service or the Authority which maintains the said Fire and Emergency Service, beyond the limits of any area in which this Act is in force for providing personnel or equipment or both, for fire-fighting purposes, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest.
Declaration of Fire and Emergency Service as Technical Service Deployment to other area	54. Without prejudice to the provisions of any other State law on the subject for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare the Fire and Emergency Service as Technical Service.
Employment on other duties	55. The Director General, Fire and Emergency Services or any Fire Officer authorized by the State Government in this behalf may, on the occasion of a fire or other emergency in any neighboring area in which this Act is not in force, order the dispatch of the employees of the Fire and Emergency Service with necessary appliances and equipment to carry out fire-fighting operations in such neighboring area and thereupon all the provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply to such areas, during the period of fire emergency or during such period as the Director General, Fire and Emergency Services or such Fire Officer as authorized by the State Government may specify on such charges as may be prescribed from time to time.
Power to obtain information	56. It shall be lawful for the State Government or any officer authorized by it in this behalf, to employ the Fire and Emergency Service in any rescue, salvage or other works for which it is suitable by reason of its training, appliances and equipment.
Power to seal buildings or premises	57. The Director General, Fire and Emergency Services or the Fire Officers employed in the Fire and Emergency Service, authorized by general or special order in this behalf may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building or other property as may be specified to supply information with respect to the character of such building or other property as may be specified, the available water supplies and means of access thereto any other material particulars, and such owner or occupier shall furnish all the information in his possession.
	58. (1) Where, on receipt of a report from the Fire Officer under section 29, or <i>suo-moto</i> , it appears to the Director General, Fire and Emergency Services that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under this Act, by order, require the person in possession or occupation of such building or premises to remove themselves from such building or premises forthwith.
	(2) If an order made by the Director General, Fire and Emergency Services under sub-section (1) is not complied with, the Director General, Fire Services may direct any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.
	(3) After the removal of the persons under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, the Director General, Fire and Emergency Services shall seal the building or premises.
	(4) No person shall remove such seal except under an order made by the Director General, Fire and Emergency Services.
	(5) Any person, who removes such seal except under an order made by the Director General, Fire and Emergency Services, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

<p>59. In fire-fighting operations or any other duties related to seizure, detention or removal of any goods involving risk of fire, it shall be the duty of a police officer or employees of the police force and other related department to assist and aid the Director or such Fire Officer in performance of such duties under this Act.</p>	<p>Police officers and others to aid</p>
<p>60. Without prejudice to the provisions contained in any other State law for the time being in force, –</p>	<p>Fire and Emergency Service functioning in the State immediately before the commencement of this Act to be deemed to be Fire and Emergency Service constituted under this Act</p>
<p>(i) the Fire and Emergency Service functioning in State before the commencement of this Act (hereinafter in this section referred to as ‘the existing State Fire and Emergency Service’) shall, on such commencement, be deemed to be the Fire and Emergency Service constituted under this Act and every member of the existing State Fire and Emergency Service holding the office, shall be deemed to be appointed and to hold the office, under this Act;</p>	
<p>(ii) all proceedings pending before any Fire Officer of the existing State Fire and Emergency Services, immediately before the commencement of this Act be deemed to be proceedings pending before him in his capacity as the holder of the office to which he is deemed to be appointed under sub-section (1) and shall be dealt with accordingly.</p>	
<p>61. In the event of the death of a member of the Fire and Emergency Services (other than a Gazetted Officer), while on duty, the State Government shall pay adequate amount to the next of kin as funeral expenses or such amount as the State Government may by an order determine.</p>	<p>Death of member of Fire and Emergency Service</p>
<p>62. Every employee of Fire and Emergency Service, acting under the provisions of this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).</p>	<p>Officers to be public servants</p>
<p>63. The State Government may call for such returns, reports and statements on any subject connected with fire prevention and fire safety, the maintenance of order and the performance of duties by the Director General, Fire and Emergency Services, Director, Fire and Emergency Services, Fire Officers, operational employees, employees and subordinate operational staff, and the same shall be furnished immediately.</p>	<p>Calling of returns, reports, statements, etc.</p>
<p>64. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.</p>	<p>Power to make rules</p>
<p>(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for, –</p>	
<p>(a) recruitment, pay and allowances and all other conditions of service of the employees of the State Fire and Emergency Services;</p>	
<p>(b) constitution of fire stations and other field formations;</p>	
<p>(c) form of certificate of appointment and Fire Officer under whose seal such certificate of appointment shall be issued;</p>	
<p>(d) mode of assessment, collection and enforcement of payment of fire tax;</p>	
<p>(e) manner in which fire tax collected shall be paid to the State Government;</p>	
<p>(f) fee on deployment of Fire and Emergency Services beyond the limits of State terms for reciprocal fire-fighting arrangements with other Fire and Emergency Services;</p>	
<p>(g) the minimum standards for fire prevention and fire safety measures, form of declaration, appeal, notice and fees under this Act;</p>	

(h) charges for extending training facilities at Fire and Emergency Services Academy to others;

(i) officers of the Fire and Emergency Service and the amount for compounding of offences ;

(j) making available to the Fire and Emergency Services with such appliances and equipment as it deems proper;

(k) the adequate supply of water to secure that it shall be available for use;

(l) constructing or providing fire stations or hiring places for accommodating the employees of the Fire and Emergency Services and its fire-fighting appliances;

(m) giving rewards to persons who have given notice of fires and to those who have rendered effective service to the Fire and Emergency Services on the occasion of fires;

(n) the training, discipline and good conduct of the employees of the Fire and Emergency Services;

(o) speedy attendance of employees of the Fire and Emergency Services with necessary appliances and equipment on the occasion of any alarm of fire;

(p) regulating and controlling the powers, duties and functions of the Director General, Fire and Emergency Services and the Director, Fire and Emergency Services;

(q) generally, for the maintenance of the Fire and Emergency Services in a due state of efficiency;

(r) regulating installation of pandals and temporary structures;

(s) writing of confidential reports of Fire Officers;

(t) determining the description and quantity of fire-fighting and rescue equipment including appliances, clothing and other necessaries to be furnished to the Fire and Emergency Services;

(u) institution, management and regulation of any Fire and Emergency Service Fund for any purpose connected with policy administration;

(v) assigning duties to Fire Officers of all ranks and grades, and prescribing the manner in which and the conditions subject to which they shall exercise and perform their respective powers and duties;

(w) generally, for the purposes of rendering the Fire and Emergency Services efficiently and preventing abuse or neglect of their duties;

(x) minimum qualification, domain knowledge and experience of qualified agency; and

(y) any other matter which is required to be, or may be, provided by the rules.

Delegation of powers

65. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification be exercisable by any of the officers of the State Government.

(2) The Director General, Fire and Emergency Services or Director, Fire and Emergency Services may, by order, direct that any power conferred or any duty imposed on him by or under this Act shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised and, performed also by any officer of the Fire and Emergency Services specified in the order.

Repeal and Savings

66. (1) The U.P. Fire Services Act, 1944, the Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005, the Uttar Pradesh Fire Services (Gazetted Officers) Service Rules, 2016, Uttar Pradesh Fire Services Subordinate Officers / Employees Service Rules, 2016 and the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Ordinance, 2022 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not be deemed to limit, modify or derogate from the general responsibility of any local authority,–

(i) to provide and maintain such water supply and fire hydrants for fire-fighting purposes as may be directed by the State Government from time to time;

(ii) to frame bye-laws for the regulation of dangerous trades;

(iii) to order any of its employees to render aid in fighting a fire when reasonably called upon to do so by any member of the fire service; and

(iv) generally to take such measures as will lessen the likelihood of fires or preventing the spread of fires.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Acts, Ordinance and rules referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

67. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before both the Houses of the State Legislature.

68.(1) The provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, in so far as the provisions relating to fire prevention and life safety are concerned.

Act to have overriding effect on other laws

(2) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, when anything in relation to the fire prevention and life safety measures is required to be done or approved under this Act, any such thing shall not be deemed to have been unlawfully done or approved by reason only of the fact that permission, approval or sanction required under such other law therefore has not been obtained.

(3) The provisions of this Act and the rules made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any other law.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3), the provisions of this Act shall be in addition to, and not, save as expressly provided hereinabove, be in derogation of the provisions of any relevant law for the time being in force in any area in which this Act is in force.

69. Where the Director General, Fire and Emergency Services or Fire Officer, who is in-charge of a fire-fighting or any emergency operation requires fire-fighting equipment and appliance or property of any other Authority or any institution or individual, he may by order requisition such equipment or property for the purpose of extinguishing fire or any other emergencies in any area and take possession thereof from the Authority or any institution or individual, as the case may be.

Requisition of Fire-fighting property

Special
promotion to the
subordinate
operational staff

70. (1) To encourage outstanding sportsmen, marks men, officers who have shown exceptional gallantry and devotion to duty in saving the life and property, the Director General, Fire and Emergency Services may, with the prior approval of the State Government, promote such officers out of turn to the next higher rank subject to availability of vacancies.

(2) Such promotions shall not exceed ten per cent of the sanctioned strength in such ranks.

(3) For purposes of seniority, such promotees shall be placed at the bottom of the promotion list drawn up for that year.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for legally and structurally equipped 'Fire and Emergency Services' in the State of Uttar Pradesh which is trained and equipped for fire prevention, life safety, rescue work and other emergencies such as flood, earthquake, building collapse, nuclear and biological hazards, etc.

In order to fulfil the aforesaid objectives, the Model Fire Service Bill, 1958 and the amended Model Fire and Emergency Bill, 2019 were circulated by the Government of India for adoption by the State Governments in order to bring uniformity in Fire Service Acts all over India.

Due to increasing industrial development, urbanization, disasters and possible fire accidents in the future, the U.P. Fire Service Act, 1944 (U.P. Act no. 3 of 1944) and the Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act, 2005 (U.P. Act no. 5 of 2005) were not able to meet the upcoming and future requirements. Also, due to Fire Safety Certificate not being an integral part of the aforesaid Acts, it was not possible to compulsorily implement fire safety system in buildings and premises.

In view of the above, it was decided to adopt the Model Fire and Emergency Bill, 2019 circulated by the Government of India by the State of Uttar Pradesh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Ordinance, 2022 was promulgated by the Governor on 28th November, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.